वर्ष : 16 ❖ अंक : 172 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
मंगलवार, 01 फरवरी 2022

चुनाव आते-जाते रहेंगे, इस सत्र को बनाएं फलदायी : पीएम मोदी 3

किसान लम्बे संघर्ष के लिए तैयार रहें : राकेश टिकैत 8

वेस्ट प्वाइंट स्कूल के पास नई बिल्डिंग का प्रस्ताव पुरानी सरकार का : विकास बस्नेत

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 जनवरी । एसडीएफ अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के बयानों का खंडन करने के लिए आज सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टी ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया। राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को एसकेएम पार्टी प्रचार-प्रसार सचिव तथा मुख्यमंत्री के गोपनीय सचिव विकास बस्नेत ने संबोधित किया।

अपने संबोधन में सचिव बस्नेत ने पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने राज्य में पर्यावरण और शिक्षा क्षेत्र में सरकार की असफलता का आरोप लगाया था। विकास बस्नेत ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जिस पुराने वेस्ट प्वाइंट स्कूल परिसर में निर्माणाधीन 14 मंजिला बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग साल 2018 में पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए पूर्व सरकार ने 05 मार्च 2019 को बीट ओपन किया था जिसमें तीन निजी कंपनियों ने भाग लिया था और यह पीपीपी मोड में ही निर्माण होने वाला था। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने यहां के कुछ कानूनी प्रक्रिया को मॉडिफाई किया है लेकिन यह प्रोजेक्ट पूर्व सरकार की ही है।

उन्होंने कहा कि निर्माण होने वाली इमारत पूर्ण रूप से पर्यावरण मैत्री, कम भार वाली और पूर्ण रूप से स्टील से निर्माण करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस परियोजना के निर्माण से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। उन्होंने जानकारी दी है कि पूर्व सरकार ने इसके लिए स्मार्ट सिटी से अप्रूवल नहीं लिया था और यह ग्रीन बिल्डिंग भी नहीं था। उन्होंने जानकारी दी है कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार ने पब्लिक सुनवाई भी आयोजित किया था। उनका कहना है कि यह राज्य में प्रथम बिल्डिंग होगी जो संपूर्ण सुविधा युक्त और सुरक्षित हो। इसे ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने भी अप्रूव किया है।

उनकी मानें तो इस बिल्डिंग के निर्माण बाद 9 रिक्टर स्केल की भूकंप भी इसे कुछ नहीं कर सकती है। विकास बस्नेत ने आगे बताया कि यहां के अस्पताल डांड़ा में निर्माणाधीन इमारत भी पूर्व सरकार के कार्यकाल 2018 में ही निर्माण के लिए अनुमति दिया गया था। इसके साथ ही पूर्व सरकार ने पुरानी एमएलए होस्टल, डेवलपमेंट एरिया स्थित यूडीएचडी विभागीय भवन भी पीपीपी मोड पर देने के लिए पूर्व सरकार ने कदम उठाया था। दूसरी ओर उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में राज्य में कुल 8630 पेड़ काटे गए थे। एसडीएफ सरकार ने नाजायज तरीके से पेड़ काटा था उन्होंने आरोप लगाया है।

उन्होंने आगे बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में गौचरन बंद होने के कारण पर्यावरण में वृद्धि हुआ था, लेकिन इसका श्रेय पवन चामलिंग को नहीं बल्कि जनता को जाता है, जिसने गौचरन के बदले में अपने जमीन पर पेड़ लगाए। उन्होंने केवल अवार्ड जीतने के लिए ही यह काम किया था। उन्होंने बताया कि साल 2006 में एसडीएफ के द्वारा आरंभ किया गया मिशन ग्रीन सिक्किम फ्लब मिशन है, आज पवन चामलिंग बताएं की किस स्थान पर मिशन के तहत लगाए गए पेड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिक्किम में बीपीएल परिवार की संख्या में कमी दिखाकर पवन चामलिंग ने केवल अवार्ड लेने का काम किया है। पत्रकार सम्मेलन को छोपेल शेरपा ने भी संबोधित किया।

सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद गंगटोक एसटीएनएम (सोकेथांग) हॉस्पिटल का भ्रमण कर मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए। उन्होंने रोगियों को फल भी वितरित किए तथा उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की।

बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय : भूटिया

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 जनवरी । शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आगामी बोर्ड परीक्षा देनेवाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। यह आरोप पूर्व एडहाक शिक्षक रिक्जिंग नर्बू भूटिया ने लगाया है। राजधानी गंगटोक स्थित जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ सिक्किम (जेयूएस) के सम्मेलन कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिक्जिंग नर्बू ने कहा कि राज्य में बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है, लेकिन अब तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है और विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम कैसा आएगा यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

वह राज्य में कार्यरत एडहॉक शिक्षक के लिए आवाज उठाते आए हैं। उनका कहना है कि एडहॉक शिक्षकों पर बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है। अन्याय अत्याचार विरुद्ध एडहॉक शिक्षकों ने राजधानी में धरना प्रदर्शन किया भी किया था।

धरना प्रदर्शन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उस समय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्याय ने शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर विभिन्न आश्वासन दिए थे। लेकिन सात-आठ महीने के बाद भी शिक्षक नियुक्ति तथा शिक्षक नियुक्ति के लिए की गई अंतरवार्ता का कोई परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इसी कारण आज राज्य के बहुत सारे विद्यालय शिक्षक के बिना ही संचालित हैं। इसके कारण विद्यार्थियों को समस्या हो रही है।

शिक्षक भूटिया ने कहा कि शिक्षकों के अभाव में आज पाठ्यक्रम अधूरा है, विद्यार्थी किस आधार पर बोर्ड परीक्षा देंगे यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के रडार में केवल राजधानी के स्कूल हैं, लेकिन राज्य के सुदूर गांव में भी स्कूल है जहां शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्वाधार के विकास और स्कूल बिल्डिंग में रंग लगा देने से शिक्षा अच्छी नहीं हो जाती है इसके लिए शिक्षक सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी गैर जिम्मेदार होने के कारण शिक्षा विभाग बेहाल है।

सरकार युद्धस्तर पर कर रही है विकास कार्य : मंत्री खरेल

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 31 जनवरी । दक्षिण जिला के नामथांग रातेपानी विधानसभा के अन्तर्गत निज रमिंग में आज क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री संजीत खरेल के हाथों उगेन थिमे वहीसिलिंग गुम्पा की आधारशिला रखी गई । एक करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से इस गुंपा का निर्माण किया जाएगा।

इसी कार्यक्रम में अन्य के अलावा क्षेत्रस्तरीय पार्टी अध्यक्ष आरएस तामांग, गुम्पा निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रह्लाद गुरुंग, भवन तथा आवस विभाग के खण्ड अभियन्ता अनिल छेत्री, एई भी उपस्थित थे। खंड अभियंता ने इस गुंपा के निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी दी।

निज रमिंग का विकास करने और पर्यटक स्थल के रूप में इसे स्थापित करने की वर्तमान सरकार की सोच के अनुसार इस गुंपा का निर्माण किया जा रहा है।

गुम्पा की आधरशिला रखने के बाद अपने संबोधन में श्री खरेल ने कहा कि अब इस गांव की रौनक में

मंत्री खरेल ने रखी गुम्पा निर्माण की आधारशिला

परिवर्तन आएगा और यहां काफी संख्या में पर्यटक आएंगे जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने यहां के लोगों की मांगों की अनदेखी की। वर्तमान सरकार जनता की मांगों को पूरे कर रही है। इस गुंपा से यहां के लोगों को फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से विकास कार्यों में सहयोग का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि इस विधानस्भा में विकास कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। किसानों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। पर्यटन के क्षेत्र में काम कर युवा रोजगार प्राख्त कर सकते हैं।

उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने को कहा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री को इसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

अब सिक्किम में होंगे दो डीआईजी रेंज

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 जनवरी । राज्य के मुख्यमंत्री तथा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग (गोले) की अध्यक्षता में रविवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। सम्मान भवन में आयोजित बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसकी जानाकारी एसकेएम प्रचार प्रसार सचिव तथा मुख्यमंत्री के गोपनीय सचिव विकास बस्नेत ने दी है।

बस्नेत ने बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब सिक्किम पुलिस में दो डीआईजी (रेंज) रहेंगे। एक डीआईजी मगन, गंगटोक और पाकिम जिला देखेंगे और दूसरे डीआईजी गेजिंग, नामची और सोरेंग जिला देखेंगे। दूसरी ओर बैठक में निर्णय लिया गया है कि गेजिंग, नामची और सोरेंग जिले के लिए पुलिस मुख्यालय जोरथांग में स्थापित किया जाएगा।

बैठक में आठ साल पूरा करने वाले एडहॉक शिक्षकों के लिए स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। आगामी मार्च महीने के अंदर राज्य के 533 एडहॉक शिक्षकों को स्थायी करने की मुख्यमंत्री गोले ने घोषणा की। बस्नेत ने जानकारी दी है कि बैठक में आगामी चार फरवरी को एसकेएम स्थापना दिवस सामान्य रूप में मनाए जाने की निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित एसकेएम स्थापना दिवस वर्तमान कोविड परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप में पालन करने का निर्णय लिया गया है। इस साल प्रत्येक जिला पार्टी कार्यालय तथा क्षेत्र क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों में पार्टी झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया जाएगा।

उन्होंने बताया है कि पार्टी अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग (गोले) उक्त दिन तिब्बत रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में उपस्थित रह सकते हैं। यह केवल संभावना है। उन्होंने कोविड परिस्थिति सही होने के बाद इसी साल के अंदर जोरथांग में चार दिवसीय पार्टी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

सीएम ने क्याब्जे दोद्रुचेन रिंपोछे के कुडंग के लिए दर्शन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 जनवरी । सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने ग्रामीण प्रबंधन विकास विभाग के मंत्री सोनम लामा के साथ आज हनुमान टोक स्थित फुन्सोक नग्यप पलरी ध्यान रिट्रीट सेंटर का भ्रमण किया। उन्होंने परम पावन क्याब्जे दोद्रुपचेन रिंपोछे के कुडुंग के भी दर्शन किए। रिंपोछे ने 25 जनवरी 2022 को महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।

मुख्यमंत्री गोले ने कहा कि रिंपोछे हमारे राज्य और बौद्ध आध्यात्मिक दुनिया के एक रत्न थे, जिन्होंने हजारों भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। आईपीआर विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार ने सभी भक्तों के लिए कुडुंग के दर्शन की व्यवस्था की है। जो 1 फरवरी, 2022 से खुलेगा। चौथे दोद्रुपचेन क्याबजे रिंपोछे के पुनर्जन्म के लिए हर जगह से प्रार्थना की जा रही है।

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने रिंपोछे के कुडुंग के दर्शन के लिए

की गई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके साथ ही दर्शन के लिए आने वाले सभी आगंतुकों के लिए स्वागत योग्य माहौल सुनिश्चित करने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर ट्रस्टी, (डोद्रुपचेन छोर्टेन ट्रस्ट), सीएल डेन्जोंग्पा, सचिव धर्म विभाग, डॉ. पासांग डी. फेम्पू, क्याबजे दोद्रुपचेन रिंपोछे के निजी सचिव, लामा अन्य अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

एसकेएम के युवाओं ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 31 जनवरी । राज्य के मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) तथा कृषि मन्त्री एवं गेजिंग बर्मेक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक लोकनाथ शर्मा से अभिप्रेरित होकर आज इस निर्वाचन क्षेत्र के चिन्थाग ग्राम पंचायत के सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी के युवाओं की ओर से पीआर लामा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित फुटबाल एकेडमी के कार्यलय में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

नाम्ची जिल्ला अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से सम्पन्न इस शिविर में सिक्किम सरकार के पशुपालन विभाग के सलाहकार दुर्गाप्रसाद प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसमें रंगीत नगर जलविद्युत परियोजना के अध्यक्ष राम कुमार छेत्री, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी गेजिंग बर्मेक क्षेत्र के युवा संयोजक एनटी शेरपा, समष्टि स्तरीय समिति के सदस्य, चिन्थाग ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बीबी गुरुंग अन्य सदस्य आदि उपस्थित रहे।

आज के इस रक्तदान शिविर में 70 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजक समिति के युवाओं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों को भी रक्तदान करते देख कर हमने उनसे प्रेरणा ली और इस शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का आयोजन युवाओं को नकारात्मक चीजों से दूर कर सकारात्मकता की ओर से ले जाना भी था। मुख्य अतिथि ने रक्तदान करने वालों को प्रमाणपत्र वितरित किया।

एमबीबीएस के राज्य कोटे के चयनित छात्रों को सौंपा गया नामांकनपत्र

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 जनवरी । राज्य शिक्षा विभाग ने एमबीबीएस राज्य कोटे की सीटों के लिए नामांकन पत्र जारी किया है। आज शिक्षा विभाग के सम्मेलन कक्ष में राज्य सरकार के प्रायोजन के तहत 50 मुक्त एमबीबीएस राज्य कोटे की सीटों के लिए चयनितों को नामांकन पत्र सौंपा गया।

शिक्षा विभाग के विशेष सचिव भीम ठ्याल ने अपने संक्षिप्त संबोधन में एमबीबीएस की 50 पूर्णत: नि:शुल्क सीटों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। जिससे राज्य कोटे के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या 80 हो गई। इसमें पहले से आवंटित 30 पूर्ण भुगतान वाली एमबीबीएस सीटें थीं। उन्होंने बताया कि यह केवल सिक्किम के छात्रों के लिए है।

उन्होंने कहा कि ये अतिरिक्त 50 सीटें सिक्किम के उन छात्रों के लिए मुफ्त होंगी जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) उत्तीर्ण करेंगे। इसमें राज्य सरकार आवास व्यय को छोड़कर पाठ्यक्रम के सभी खर्चों का भुगतान करेगी। इसको सिक्किम के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए ठटाल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के नेतृत्व में इस विकास से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ होगा। उनके लिए चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर होंगे। उन्होंने 50 चयनित छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

चुनाव आयोग ने अधिकतम 1000 लोगों के साथ रैलियों की अनुमति दी

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों पर प्रतिबंध को 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है।

हालांकि, इसने 1 फरवरी से सभी चरणों के लिए अधिकतम 1,000 व्यक्तियों (मौजूदा 500 के बजाय) या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा निर्धारित सीमा या निर्धारित (शेष पृष्ठ ०३ पर)

कोरोना महामारी के दौरान भारत में कोई भूखा नहीं सोया : राष्ट्रपति कोविंद

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। बजट से पहले अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना के दौरान सरकार के द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख एवं प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई आपदा में भारत में कोई भूखा नहीं सोया। कोरोना सरकार ने करोड़ों देशवासियों के लिए निशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की। राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति, इंफ्रास्ट्रक्च र, कृषि विकास, स्टार्ट अप और नई टेक्नोलॉजी के साथ-साथ भारत की प्राचीन संस्कृति का महत्व भी रेखांकित किया।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोरोना के महासंकट में हमने कई बड़े-बड़े देशों में भूख की समस्या देखी है लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार इस बात का पूरा प्रयास किया कि इस बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। 2,60000 करोड रुपए के खर्च के साथ करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारी सरकार ने इस योजना को अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है।

राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति का विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आकार देने के लिए सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो गई है।

आईटीआई और प्रधान मंत्री कौशल केंद्र के जरिए पूरे देश में सवा दो करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। यूजीसी के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े छह विशेष शिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इससे हेल्थ केयर सेंटर को मदद मिल रही है। जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए आदिवासी बहुल एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह स्कूल करीब 3.30 लाख जनजातीय युवाओं को शैक्षणिक तौर पर सशक्त बनाएंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कारों के चयन में भारत सरकार की भावना दिखाई पड़ती है।

एक योजना के तहत अभी तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को सहायता दी जा चुकी है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल भी शुरू किया है जिससे अभी तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हम लगातार देख रहे हैं 44 करोड़ से अधिक देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को भी कैश पहुंचाया जा सका। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इक्नॉमी और डिजिटल इंडिया के बढ़ते प्रसार और यूपीआई के बढ़ते चलन के लिए भी मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार गरीब की गरिमा बढ़ाने को महत्वपूर्ण मानती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विगत 3 वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की लागत से 17,000000 घर स्वीकृत किए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य शुरू किए गए जल जीवन मिशन में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है।

महामारी की बाधाओं के बावजूद करीब 6 करोड़ ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ा गया है।

इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव की महिलाओं बेटियों और बहनों को हुआ है।

स्वामित्व योजना भी एक असाधारण प्रयास है इस योजना के तहत 28000 गांव में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। यह प्रॉपर्टी कार्ड न केवल विवादों को रोकने में सहायक हैं बल्कि गांव के लोगों को बैंकों से ऋण मिलना भी आसान हो रहा है।

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण के दौरान भारत की नई शिक्षा नीति और शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग तीन करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे साढ़े चार करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है।

राष्ट्रपति ने कहा, देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। यह हर्ष की बात है कि मौजूदा सभी 33 सैनिक स्कूलों ने बालिकाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी महिला कैडेट्स के प्रवेश को मंजूरी दी है। महिला कैडेट्स का पहला बैच एनडीए में जून 2022 में प्रवेश करेगा। मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत के संकल्प व सामर्थ्य को आकार देने के लिए मेरी सरकार, देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है।

स्किल इंडिया मिशन के तहत, आई.टी.आई., जन शिक्षण संस्थान, और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के जरिए पूरे देश में सवा दो करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास हुआ है। स्किल को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए यू.जी.सी. के नियमों में कई बदलाव भी किए गये हैं।

कोरोना से लड़ाई के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत हेल्थ केयर से जुड़े 6 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनसे हेल्थ केयर सेक्टर को मदद मिल रही है।

सरकार द्वारा जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल

के विस्तार का काम किया जा रहा है। ये स्कूल लगभग साढ़े तीन लाख जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाएंगे।

सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरूआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर, केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रेकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रेकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रेकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई जिससे एक करोड़ तीस लाख किसान लाभान्वित हुए।

सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रेकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है।

हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन भी किसानों के लिए आमदनी के नए स्रोतों और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुँच के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने से वर्ष 2020-21 में देश का शहद उत्पादन एक लाख पच्चीस हजार मीट्रिक टन तक पहुँच गया है जोकि 2014-15 की तुलना में करीब 55 प्रतिशत ज्यादा है। 2014-15 की तुलना में शहद की निर्यात मात्रा में भी 102 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।

किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिलें, इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुँचना जरूरी होता है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू करते हुए किसानों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। कोरोना काल में भारतीय रेल ने सब्जियों, फलों तथा दूध जैसी, जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए, 150 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज्यादा किसान रेल चलाईं और करीब 6 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की। यह इस बात का उदाहरण है कि अगर सोच नई हो तो पुराने संसाधनों से भी नए रास्ते बनाए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से दी राहत

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स के एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी है।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि वह अपनी सरकार को चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आपराधिक मामले शुरू करने से परहेज करने की सलाह दें। शीर्ष अदालत ने मजीठिया को 24 फरवरी को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया।

पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि पंजाब नशे के कारोबार में डूब रहा है और युवा खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का मामला है और पैसे के लेन-देन हुए हैं, जहां मजीठिया ने मध्यस्थता की और हिरासत में पूछताछ के लिए दबाव डाला।

मुख्य न्यायाधीश ने चिदंबरम से कहा कि आरोप है कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है और पूछा कि चुनाव कब खत्म होंगे? उन्होंने पंजाब के एक विधायक के एक अन्य मामले का उल्लेख करने की ओर इशारा किया, जहां उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले का हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव से पहले अचानक ऐसे मामले सामने आते हैं और अदालत का यह मतलब नहीं है कि सरकार को ड्रग माफिया पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

पीठ ने कहा, 'उन्हें नामांकन और प्रचार करने दें, एक बार यह खत्म हो जाने पर वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और नियमित जमानत के लिए आवेदन करेंगे।'

मजीठिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि छह साल तक पूरी तरह से जांच की गई और उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला।

शिअद प्रमुख सुखबीर बादल के करीबी रिश्तेदार मजीठिया 20 फरवरी को अमृतसर के पास मजीठा से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं। मोहाली की एक अदालत ने 20 दिसंबर को दर्ज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।

राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मोहाली पुलिस स्टेशन में दर्ज 49 पन्नों की प्राथमिकी में शिअद नेता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

करहल से अखिलेश को चुनौती देंगे बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल

लखनऊ, 31 जनवरी (एजेन्सी)। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार होंगे।

सोमवार को मैनपुरी में अखिलेश यादव के पर्चा दाखिल करने के एक घंटे बाद बघेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

दिलचस्प बात यह है कि बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के लिए सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया था।

यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर और पांच बार सांसद रहे बघेल ने अपने करियर में कई मुकाम हासिल किए हैं।

औरैया जिले के रहने वाले बघेल को उनके काम के लिए जाना जाता है। वह 1998, 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में लोकसभा के सदस्य थे, जो जलेसर सीट का प्रतिनिधित्व करते थे।

2009 में, बघेल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गए और बसपा के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए।

लेकिन 2014 में, फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव में लड़ने के बाद बघेल ने बसपा के राज्यसभा सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया।

इसके तुरंत बाद, उन्होंने खुद को भाजपा के साथ जोड़ लिया। 2015 में, उन्हें भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

2017 में, उन्होंने टूंडला से विधानसभा चुनाव जीता और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री का पद संभाला।

2019 में, उन्हें भाजपा द्वारा आगरा लोकसभा सीट (एससी) से मैदान में उतारा गया था। बघेल दूसरे उम्मीदवार से दो लाख से अधिक मतों से वहां जीते थे।

बीजेपी वाले नहीं जानते इतिहास : जयंत चौधरी

लखनऊ, 31 जनवरी (एजेन्सी)। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे करीब आ रही हैं, वैसे-वैसे एक दूसरे पर हमले तेज हो रहे हैं। बीजेपी और सपा-रालोद गठबंधन के बीच लगातार हमले जारी हैं। अमित शाह की तरफ से मिले न्योते और अब धमेंद्र प्रधान के बयान पर जयंत चौधरी ने सवाल खड़ा किया है। जयंत ने कहा कि 42 साल की मेरी उम्र है और 20 साल से राजनीति में हूं। इससे पहले भाजपा ने क्यों न्योता नहीं दिया। जयंत ने कहा कि वह लोग केवल सपा-रालोद को तोड़ना चाहते हैं। सपा-रालोद गठबंधन से भाजपा बुरी तरह डरी हुई है।

अमित शाह ने पिछले दिनों जाट नेताओं से मुलाकात के बाद कहा था कि जयंत चौधरी ने गलत घर का चुनाव कर लिया है और चुनाव बाद भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के इस न्यौते को ठुकराते हुए कहा था कि वह चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएं। इसके बाद शाह ने एक जनसभा में यह भी कहा कि चुनाव बाद अखिलेश यादव जयंत चौधरी का साथ छोड़ देंगे।

सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान ने भी जयंत चौधरी के चवन्नी वाली बयान पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह बच्चे हैं। प्रधान ने उनके पिता के बार-बार पार्टी बदलने की याद दिलाते हुए कहा कि उनका इतिहास ज्ञान बेहद कमजोर है। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें बच्चा बताते हुए माफ करने की बात कही।

प्रधान ने आगरा में कहा, ''जयंत के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। वह (जयंत चौधरी) बच्चे हैं, वह मैदान में नए आए हैं। उनके पिता ने कितनी बार पार्टी बदली। जब वह पहली बार चुनाव लड़े तो किसके साथ

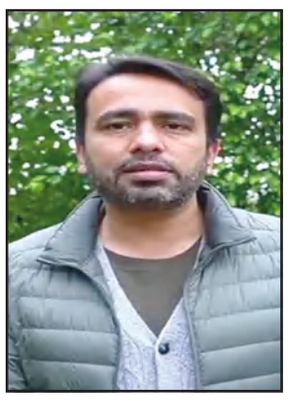

गठबंधन था। मुझ नहीं पता था कि उनका इतिहास ज्ञान इतना कमजोर है। बच्चों को माफ कर देना चाहिए।''

देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजित सिंह ने साल 1980 में राजनीतिक सफर का आगाज किया था। पिछले साल कोरोना की वजह से निधन से पहले करीब तीन दशक के लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने कई बार अलग-अलग दलों से गठबंधन किया। 1999 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके अजित सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने तो 2002 में उन्होंने गठबंधन तोड़कर 2004 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन किया।

2007 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी की राहें फिर अलग हो गईं। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 2011 में अजित सिंह यूपीए-2 का हिस्सा बहनकर मंत्री बने। 2014 के लोकसबा चुनाव में भी आरएलडी कांग्रेस के साथ लड़ी। 2017 में कांग्रेस और सपा के साथ आने पर आरएलडी को दरकिनार कर दिया गया तो 2019 के लोकसबा चुनाव में रालोद को बसपा और सपा गठबंधन का हिस्सा बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने रालोद से गठबंधन किया है।

पेगासस को लेकर चिदंबरम का केंद्र पर निशाना, कहा- हमें यदि उन्नत स्पाईवेयर मिले तो हम उन्हें 4 अरब डॉलर दे सकते हैं

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए उनकी इस टिप्पणी का उल्लेख किया कि भारत-इजराइल संबंधों में नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है।

चिदंबरम ने कहा कि इजराइल से यह सवाल करने का सबसे अच्छा समय है कि क्या उनके पास पेगासस स्पाईवेयर का कोई उन्नत संस्करण है।

सरकार पर चिदंबरम का यह हमला न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर के एक दिन बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि इजराइली स्पाईवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली भारत-इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे के ''केंद्र बिंदु'' थे। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर अवैध जासूसी करने में संलिप्त रहने का आरोप लगाया था और इसे देशद्रोह करार दिया था।

चिदंबरम ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत-इजराइल संबंधों में नए लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे अच्छा समय है। बेशक, यह इजराइल से पूछने का सबसे अच्छा समय है कि क्या उनके पास पेगासस स्पाईवेयर का कोई उन्नत संस्करण है।

पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा, पिछला सौदा 2 अरब अमेरिकी डॉलर का था। भारत इस बार बेहतर कर सकता है। अगर हमें 2024 के चुनावों से पहले और अधिक परिष्कृत स्पाईवेयर मिलता है, तो हम उन्हें 4 अरब डॉलर भी दे सकते हैं।

भारत और इज़राइल के बीच कूटनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर शनिवार को एक विशेष वीडियो संदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत और इजराइल के आपसी संबंधों को और आगे ले जाने और नए लक्ष्य निर्धारित करने का इससे बेहतर समय कुछ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों के मद्देनजर दोनों देशों के आपसी संबंधों का महत्व और बढ़ गया है।

चिदंबरम ने अंग्रेजी अखबार को सुपारी मीडिया कहने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह पर भी निशाना साधा।

चिदंबरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा, मंत्री वी के सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को 'सुपारी मीडिया' कहा है। क्या वह व्यक्ति नहीं हैं, जिसने भारतीय मीडिया को 'प्रेस्टीट्यूट्स' कहा था?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, मैं सोचता हूं कि क्या उन्होंने कभी न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट जैसे समाचार पत्र पढ़े हैं। मुझे संदेह है कि क्या वह वाटरगेट घोटाले और पेंटागन पेपर्स को उजागर करने में दोनों समाचार पत्रों द्वारा निभाई गई भूमिका को जानते हैं। यदि वह इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वह कम से कम फिल्में तो देख सकते हैं!

सिंह ने जहां एक ओर द न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया कहा था, वहीं एक सरकारी सूत्र ने कहा था कि पेगासस सॉफ्टवेयर से संबंधित मामले की निगरानी उच्चतम न्यायालय के तहत एक समिति द्वारा की जा रही है, जिसका नेतृत्व शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

पाक में दाऊद की मौजूदगी का संकेत

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। देश की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने आरोप लगाया है कि खाड़ी में रहने वाला पाकिस्तानी कारोबारी उमर फारूक जहूर, दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है। पाकिस्तान के लिए यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है।

रिजवान रजी द्वारा पाकिस्तान में अपलोड किए गए एक यूट्यूब वीडियो में कहा गया है कि फारूक जहूर वांछित आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का साथी है।

भारत लगातार सवाल उठाता रहा है कि दाऊद कहां है, जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि वह इस मुल्क में नहीं है।

रजी ने कहा कि जांच पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी और एफआईए प्रमुख सनाउल्लाह अब्बासी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जहूर दाऊद का साथी है।

रजी ने कहा कि इससे इंटरपोल अब्बासी से पूछ सकता है, क्योंकि कई नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि दाऊद वहां नहीं है।

रजी ने एक ब्लॉग में कहा कि इस खुलासे के बाद अब्बासी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि उसे कहां छिपाया गया है, क्योंकि दाऊद पर गोपनीयता बनाए रखने की उसकी लंबे समय से चली आ रही नीति का उल्लंघन किया गया है।

द न्यूज ने पहले बताया था कि नॉर्वे में वित्तीय अपराधों में वांछित एक संदिग्ध जहूर, जिसे अब पूर्व डीजी एफआईए बशीर मेमन के साथ जोड़ा जा रहा है, इमरान खान सरकार के दौरान हाई-प्रोफाइल बैठकों में भाग लेते पाया गया है, आधिकारिक तौर पर जारी किए गए पिक्चर शो से यह स्पष्ट है। एफआईए के रिकॉर्ड के अनुसार, उसने 14 वर्षों (2006-2019) में 60 से ज्यादा बार पाकिस्तान का दौरा किया।

रिकॉर्ड आगे बताता है कि नार्वे के अधिकारियों द्वारा नियत अवधि के भीतर इंटरपोल के सवालों का जवाब नहीं देने के बाद इंटरपोल ने जहूर के खिलाफ रेड नोटिस रद्द कर दिया था और मेमन ने केवल अर्जी को आगे बढ़ाया था, जब वह (मेमन) डीजी, एफआईए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह पता चला है कि अगर जहूर को दंडित करने के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकलता है, तब एफआईए अपने पूर्व बॉस को एक और जांच में फंसा सकता है।

द न्यूज ने बताया कि जहूर मध्य-पूर्वी राज्य के शाही परिवार

के एक महत्वपूर्ण सदस्य का करीबी विश्वासपात्र है और पाकिस्तान में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मिलने या भाग लेने के दौरान शाही परिवार के सदस्य के साथ अलग-अलग तस्वीरों में उसे देखा गया है। अब, जैसा कि सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त किए गए गैरकानूनी आदेश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मेमन के चारों ओर फंदा कसने के लिए तैयार है, जहूर के साथ उसकी तस्वीर को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें शाही परिवार का सदस्य भी मौजूद था।

डीलशेयर ने अपनी सीरीज ई फंडिंग के पहले समापन की घोषणा की

सिलीगुड़ी, 31 जनवरी । 3 साल पुराने सोशल ई-कॉमर्स स्टार्ट-अप डीलशेयर ने घोषणा की कि उसने अपनी सीरीज ई फंड जुटाने के पहले करीब 165 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने मौजूदा निवेशकों टाइगर ग्लोबल और अल्फा वेव ग्लोबल (फाल्कन एज) से निरंतर प्रतिबद्धताओं के साथ ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, कोरा कैपिटल और यूनिलीवर वेंचर्स का स्वागत किया। इस दौर में जुटाई गई धनराशि का उपयोग प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में निवेश करने के साथ-साथ इसके रसद बुनियादी ढांचे में दस गुना विस्तार और भौगोलिक पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, यह एक बड़ा ऑफलाइन स्टोर फ्रैंचाइजी नेटवर्क स्थापित करेगा।

डीलशेयर उच्च गुणवत्ता वाली, कम कीमत वाली आवश्यक चीजें प्रदान करता है, जो एक गेमीफाइड, मस्ती से भरे और वायरलिटी-ड्रिवन खरीदारी अनुभव के साथ मिलती है, जिससे पहली बार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव करना आसान हो जाता है। डीलशेयर के संस्थापक और सीईओ विनीत राव ने कहा, 'डीलशेयर भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है। पिछले साल मुनाफे में सुधार के साथ हमारे रेवेन्यु और कस्टमर बेस में 13 गुना वृद्धि हुई है। एक मजबूत ग्राहक आधार के साथ 10 मिलियन, हमने 10 राज्यों के 100 से अधिक शहरों में अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार किया है।

हमारी कंपनी ने देश भर में 5000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।' डीलशेयर की स्थापना विनीत राव, सौरज्येंदु मेद्दा, शंकर बोरा और रजत शिखर ने 2018 में की थी। यह उन 10 राज्यों में 100 से अधिक गोदामों का संचालन करता है, जिनमें यह संचालित होता है, और अगले 12महीने अपने वेयरहाउसिंग को आज 2 मिलियन वर्ग फुट से बढ़ाकर 20 मिलियन वर्ग फुट करने की योजना है।

चुनाव आते-जाते रहेंगे, इस सत्र को बनाएं फलदायी : पीएम मोदी

राजेश अलख

नई दिल्ली, 31 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील करते हुए कहा है कि पांच राज्यों में चल रहे चुनाव का असर इस बजट सत्र पर नहीं पड़ना चाहिए।

संसद के बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से सदन चलने देने की अपील करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव की वजह से संसद का सत्र भी प्रभावित होता है और चचार्एं भी प्रभावित होती है, लेकिन इसका असर बजट सत्र पर नहीं पड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। यह देश के विकास को लेकर साल भर का खाका खींचता है। इसलिए बजट सत्र को सांसद जितना फलदायी बनाएंगे, जितने अच्छे मकसद से चर्चा करेंगे , आने वाले वर्ष में भारत को नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का उतना ज्यादा अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में भारत की बढ़ रही प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद हैं।

भारत की आर्थिक प्रगति और स्वदेशी वैक्सीन से दुनिया भर में भारत को लेकर विश्वास पैदा हो रहा है।

नौकरी निकलने पर लूट को निकलते थे चाचा-भतीजा : योगी

आगरा, 31 जनवरी (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा शासन में भर्तियां निकलने पर चाचा-भतीजा और परिवार वसूली करने निकल पड़ता था। लूट-खसोट होती थी। तबादलों के नाम पर पैसे वसूलते थे। माफियाओं को छूट मिलती थी। आगरा के जाटलैंड और क्षत्रियों की बाईसी में प्रभावी मतदाता सम्मेलनों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में पांच लाख युवाओं को नौकरी और एक करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा के किरावली, शमसाबाद और आंवलखेड़ा में सम्मेलनों को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किए और लाल टोपी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि सपा की लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगी हुई है। सपा शासन में हर तीसरे दिन दंगा होता था। योगी ने परोक्ष रूप से सन् 1990 के अयोध्या गोली कांड का जिक्र किया। कहा कि रामभक्तों पर गोली चलाने का पाप सपा के ऊपर है।

सीएम योगी ने सपा के अलावा बसपा और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। इन पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची पर निशाना साधा। कहा कि अपराधियों और दंगाइयों को टिकट देने की होड़ लगी है। जब-जब सपा और बसपा की सरकार बनी, इन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने के षड्यंत्र रचे। इस बार सूबे में डबल इंजन की सरकार है जिसमें गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। दस मार्च को जब यूपी में पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी तो जनता को धमकाने वाले सपा-बसपा के प्रत्याशियों और माफिया पर फिर से बुलडोजर चलेगा।

तेजस्वी को कांग्रेस का जवाब, सभी 24 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार

पटना, 31 जनवरी (का.सं.)। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी स्थानीय निकाय कोटे से होने वाली सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने वैसे उम्मीदवारों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जहां वह सहयोगी दलों के लिए मदद करना चाह रही थी। अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश नेतृत्व को आलाकमान के निर्देश का इंतजार है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि फरवरी-मार्च में होने जा रहे बिहार विधान परिषद की सभी 24 स्थानीय निकायों की सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी आलाकमान हमें दूसरी लाइन का पालन करने के लिए नहीं कहता, तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। बता दें कि रविवार को अजीत शर्मा ने कहा था कि महागठबंधन खत्म नहीं हो सकता। यह गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बना था। अकेले लड़ने का मतलब यह नहीं कि महागठबंधन समाप्त हो गया। कांग्रेस का जनाधार मजबूत है और आगे भी होगा।

वहीं दिल्ली में कई दिनों से जमे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने कहा कि राज्य में बड़ी पार्टी होने के नाते राजद की यह जिम्मेदारी थी कि वह समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। एक समय लालू प्रसाद ने कांग्रेस को छह-सात सीट देने की बात कही थी। अब तेजस्वी यादव कुछ और बयान दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है। हम सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पहले छह-सात सीटों पर

उम्मीदवारों को हरी झंडी दी गई थी। अब सभी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। आलाकमान को पूरे घटनाक्रम की सूचना दे दी गई है।

स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव में राजद की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस के बगैर राजद एमएलसी का चुनाव लड़ती है तो उसकी बड़ी हार तय है। साथ ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की सारी संभावनाएं भी समाप्त हो जाएगी। अनिल शर्मा ने सोमवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में एमएलसी पद के लिए कांग्रेस के बिना राजद चुनाव लड़ेगा तो 2021 के विधानसभा उपचुनाव, 2009 के संसदीय चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव की तरह ही राजद की बड़ी हार होगी। साथ ही 2025 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सीएम बनने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी।

सीएम योगी ने औरंगजेब और गोकुल जाट के बहाने सपा पर साधा निशाना

लखनऊ, 31 जनवरी (एजेन्सी)। सीएम योगी ने सोमवार को एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की। औरंगजेब और गोकुल जाट का नाम लेकर सपा सरकार को घेरा और जमकर हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार ने औरंगजेब को धूल चटाने वाले गोकुल जाट का सम्मान नहीं किया। हमारी सरकार ने आगरा के म्यूज़ियम का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा। सीएम योगी सोमवार को आगरा में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में बेटियों की सुरक्षा में खेल होता था पर अब प्रदेश में दंगा करने वाले 10 बार सोचते हैं कि दंगा करेंगे तो बाप दादा की कमाई संपत्ति बिक जाएगी और पोस्टर अलग चस्पा होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा आस्था का सम्मान करती है लेकिन सपा आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। पहले चाचा, भतीजे महाभारत के सभी रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पहले ट्रांसफर, पोस्टिंग और तो और युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी लोग उगाही करते थे। सपा की सूची दंगाइयों, अपराधियों और तो और माफियाओं से भरी है। प्रदेश के 5 लाख नौजवानों को नौकरी, या प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार देने के कार्य हमारी भाजपा सरकार ने किया है।

सीएम योगी ने कहा कि सपा की टोपी मुफ्फरनगर दंगों में मारे गए निर्दोष लोगों के खून से रंगी है। सपा को जब भी मौका मिला इन्होंने प्रदेश को दंगों में झोंका, योजनाओं में बंदरबाट किया। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम इन सपा-बसपा ने किया। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लागू किया। जिसका परिणाम है कि आज हर गरीब किसान को लाभ मिल रहा है। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी का लाभ देने का काम किया है। मथुरा में हमने एक लाख आलू की प्रोसेसिंग की यूनिट हमने लगाने का काम किया।

जो सपा संरक्षित माफिया गुंडे टिकट लेकर जनता को धमकाने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 10 मार्च के बाद वही बुलडोज़र चलने को तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के साथ आपके सामने है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश के बेहतर कोरोना प्रबंधन का परिणाम विश्व ने देखा है। प्रदेश में निशुल्क टीका, टेस्ट, दवाएं, इलाज के साथ डबल इंजन वाली सरकार ने राशन की डबल डोज देने का काम भी कुशलतापूर्वक किया। कोरोना संकट के दौरान जिस सपा बसपा का पता नहीं था वो कैसे सहयोगी जो संकट के समय साथ न दें।

चुनाव आयोग ने .....

सीमा के 50 प्रतिशत के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों में पार्टियों या उम्मीदवारों की भौतिक सार्वजनिक बैठकों की अनुमति देने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने कहा कि आयोग ने पोल पैनल ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार की सीमा भी बढ़ा दी है, जिसमें अब तक सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर 20 लोगों को अनुमति दी गई है, जबकि अब तक 10 लोगों को अनुमति थी। दूसरे निर्देश पहले की तरह बने रहेंगे।

आयोग ने अब पार्टियों के लिए इस हद तक छूट दी है कि इनडोर बैठकों में अब अधिकतम 500 व्यक्ति (मौजूदा 300 के बजाय) या हॉल क्षमता का 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित निर्धारित सीमा हो सकती है, जबकि पार्टियां / उम्मीदवार चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड के उचित व्यवहार और दिशा-निदेशरें और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी शेष प्रतिबंध, जैसा कि 8 जनवरी को जारी चुनाव के संचालन के लिए संशोधित व्यापक दिशानिर्देश, 2022 में निहित है, पहले की तरह जारी रहेगा।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ सोमवार को विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में कोविड -19 की वर्तमान स्थिति की एक और व्यापक समीक्षा की।

आयोग, महासचिव और उप चुनाव आयुक्तों के साथ, वर्तमान स्थिति और महामारी की अनुमानित प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, वर्चुअल मोड के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिवों और पांच चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की।

अधिकारियों ने कहा, संबंधित राज्यों में पात्र व्यक्तियों के लिए पहली और दूसरी खुराक की वर्तमान टीकाकरण स्थिति के साथ-साथ मतदान कर्मियों की व्यवस्था के संबंध में भी गहन चर्चा हुई।

सभी मुख्य सचिवों ने आयोग को अपने-अपने राज्यों में कोविड-19 की स्थिति से अवगत कराया और बताया कि कैसे अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में कमी आने के साथ ही सकारात्मकता दर में गिरावट दिख रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल सावधानियों को जारी रखने की आवश्यकता है ताकि राजनीतिक गतिविधियों के कारण तीव्र सार्वजनिक संपर्क के कारण कोरोना मामले नहीं बढ़ सकें।

राष्ट्रपति कोविंद के संबोधन में चीन और पाकिस्तान का जिक्र नहीं : कांग्रेस

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। कांग्रेस ने सोमवार को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चिंता जताई और कहा कि राष्ट्रपति ने चीन और पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, जिन दो मोर्चे पर भारत लगातार जूझ रहा है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ने नागालैंड में हुई हत्याओं का भी कोई जिक्र नहीं किया है।

कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने कोविड की मौतों पर माफी नहीं मांगी है और सवाल किया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई उल्लेख क्यों नहीं है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'चीन/पाक/दो मोर्चे की स्थिति पर एक शब्द नहीं। नागालैंड में नागरिकों के नरसंहार पर कोई खेद नहीं है। जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई घोषणा नहीं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, भारत पर इसके आतंकी प्रभाव अस्पष्ट हैं। दूसरी लहर में हुई मौतों पर कोई माफी नहीं।'

कांग्रेस इस बात से खफा है कि सरकार चीन के साथ एलएसी पर चुनौती का सामना कर रही है और खबरें हैं कि चीन अरुणाचल सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। पार्टी चाहती थी कि राष्ट्रपति उस मोर्चे पर सरकार के प्रयासों की रूपरेखा सामने रखें।

हालांकि राष्ट्रपति ने दुनिया में सरकार की राजनयिक पहुंच का उल्लेख किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि भारत ने राजनयिक संबंधों में सुधार के माध्यम से तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक वातावरण में अपनी स्थिति मजबूत की है।

बजट सत्र की शुरूआत में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 'भारत ने राजनयिक संबंधों में सुधार के माध्यम से तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक वातावरण में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत ने अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।'

राष्ट्रपति कोविंद ने उल्लेख किया कि भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापक बहस की।

उन्होंने कहा, 'भारत की अध्यक्षता में, पहली बार, सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर एक व्यापक बहस की।'

पड़ोस में मौजूदा स्थिति के बारे में बात करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा, 'हमने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अस्थिरता देखी है। मौजूदा स्थिति के बावजूद, मानवता की भावना के अनुरूप, भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू की।'

'चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, हमने काबुल से अपने कई नागरिकों और कई अफगान हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया। हम कठिन परिस्थितियों के बीच पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के दो स्वरूपों को भी सुरक्षित वापस लाए।' चुराई गई कलाकृतियों को वापस लाने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य विरासत को देश में वापस लाया जाए। मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, जो भारत से चुराई गई थी। सौ साल पहले, वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। ऐसे कई ऐतिहासिक कलाकृतियों को विभिन्न देशों से भारत वापस लाया जा रहा है।'

94 वर्षीय बादल ने चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा

चंडीगढ़, 31 जनवरी (एजेन्सी)। पंजाब के पांच बार के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने सोमवार को पंजाब के मुक्तसर जिले की विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वह 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को होने वाले चुनाव में 94 साल के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं।

लांबी निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे बुजुर्ग बादल 1995 से 2008 तक शिअद के अध्यक्ष रहे। बादल ने इस सीट से 2017 का विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह को 22,770 मतों से हराकर जीता था।

अकाली मुखिया ने 1997 में लांबी से चुनाव लड़ना शुरू किया था और इस सीट को 28,728 मतों से, 2002 में 23,929 मतों से, 2007 में 9,187 मतों से चुनाव जीता था। 2012 में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 24,739 मतों से हराया था।

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय

तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली 110011

नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, तीन मूर्ति परिसर में, प्रधानमंत्री संग्रहाय विकसित कर रहा है। एनएमएमएल निम्नलिखित के लिए ई-बोली आमंत्रित करता है:

एमओपीएम/आरएफपी/2022/003V4 राजस्व बंटवारे के आधार पर एक स्मारिका दुकान की स्थापना और संचालन। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक है।

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट **www.nehumemorial.nic.in, www.tenderwizard.com/NMML, www.eprocure.gov.in** देखें।

davp 09142/12/0026/2122

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR SUN MONDAY
Draw No:62 DrawDate on:31/01/22
1st Prize ₹1 Crore/- 86C 28528
Cons. Prize Rs.1000/- 28528 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
04092 15778 38687 43599 49080 73511 00079 83440 87169 99748
3rd Prize ₹450/-
0812 2852 5972 6151 6155 6410 6720 7047 7989 8151
4th Prize ₹250/-
0979 1211 2011 2851 4977 5388 6127 9564 9891 9947
5th Prize ₹120/-
0067 0261 0389 0429 0460 0474 0514 0535 0587 0719
0992 1000 1328 1542 1648 1754 1796 1824 1932 2105
2135 2206 2259 2337 2437 2592 2864 3112 3115 3199
3380 3450 3671 3675 3783 3814 4154 4160 4265 4281
4330 4517 4690 4763 4863 4936 4965 4985 5078 5184
5187 5245 5272 5562 5799 5837 5997 6085 6215 6240
6245 6246 6347 6368 6390 6417 6486 6590 6662 6766
6817 6827 6906 6953 6962 7096 7099 7152 7213 7538
7599 7732 7756 7783 7901 8292 8304 8433 8564 8609
8698 9044 9185 9326 9418 9420 9430 9469 9569 9921
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR GANGA MORNING
Draw No:62 DrawDate on:31/01/22
1st Prize ₹1 Crore/- 49B 67522
Cons. Prize Rs.1000/- 67522 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
22903 35687 37064 39955 41617 41881 46726 77596 85075 98328
3rd Prize ₹450/-
0594 4961 5889 8090 8456 8819 8887 9634 9681 9759
4th Prize ₹250/-
1033 1810 2511 5368 7568 8149 8297 8503 8626 8844
5th Prize ₹120/-
0131 0137 0303 0528 0662 0835 0918 1055 1251 1256
1304 1527 1580 1605 1686 1710 1751 1769 1784 2052
2121 2182 2246 2295 2331 2342 2359 2479 2526 2577
2618 2727 2921 3082 3121 3136 3182 3242 3246 3271
3300 3350 3364 3618 3861 3934 3937 4000 4064 4185
4252 4263 4294 4399 4496 4500 4574 4713 4746 4859
4946 4995 5072 5314 5353 5548 5939 5992 6092 6266
6268 6304 6455 6523 6709 6867 7127 7136 7204 7205
7303 7318 7528 7731 7816 8064 8195 8250 8449 8355
9223 9349 9412 9454 9514 9607 9690 9806 9867 9916
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR FLAMINGO EVENING
Draw No:162 DrawDate on:31/01/22
1st Prize ₹1 Crore/- 44H 45280
Cons. Prize Rs.1000/- 45280 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
23670 28172 44399 49290 52207 59592 65059 81141 90242 92039
3rd Prize ₹450/-
0167 0999 3493 4721 6354 6475 7073 8328 8628 9745
4th Prize ₹250/-
2939 3454 4451 4637 5460 5683 5940 8864 9841 9936
5th Prize ₹120/-
0117 0151 0239 0319 0386 0468 0651 0755 0744 0787
0848 0987 1084 1088 1194 1430 1462 1491 1521 1671
1952 2023 2041 2087 2141 2372 2442 2493 2602 2603
2619 3175 3562 3684 3709 3717 3762 3805 4028 4043
4108 4250 4423 4634 4639 4646 4733 4774 4845 5024
5242 5249 5290 5306 5301 5399 5432 5587 5589 5623
5897 5993 6157 6174 6175 6216 6264 6339 6428 6496
6562 6680 6704 6750 7159 7220 7232 7422 7436 7606
7634 7802 8314 8657 8702 8727 8735 8741 8798 8806
8926 8960 8971 9111 9127 9147 9223 9315 9609 9854
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR 100 EAGLE MONDAY
Draw No:3 DrawDate on:31/01/22
1st Prize ₹20LAKHS/- 69543
2nd Prize ₹9000/-
0062 0143 2576 3075 3084 3246 3856 5804 7946 8696
3rd Prize ₹5000/-
0463 1380 1869 2266 3485 4031 5874 6805 7305 7701
4th Prize ₹2000/-
2641 3297 3708 3907 4141 5272 7976 8160 8706 9157
5th Prize ₹1000/-
0161 0434 1673 1733 3071 3898 5231 6274 6777 9905
6th Prize ₹500/-
0127 0368 0676 0795 0808 0818 1019 1196 1346 1379
1384 1467 1796 1827 1845 1863 1928 1934 2503 2543
2636 2671 2679 2740 2746 2785 2787 2904 2995 3035
3068 3137 3138 3198 3226 3442 3512 3617 3673 3674
3742 3745 3768 3774 3782 4012 4086 4176 4181 4275
4353 4528 4744 4774 4798 4828 4908 4954 5020 5066
5068 5069 5179 5346 5378 5451 5469 5723 6204 6490
6587 6611 6755 6813 7112 7159 7172 7367 7380 7506
7705 7746 7747 8096 8229 8300 8327 8426 8439 8441
8465 8493 8745 8759 9387 9413 9452 9658 9692 9706
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES
Draw Time: 07:00 PM
LABHLAXMI RUBY MONDAY
Draw No:3 DrawDate on:31/01/22
1st Prize ₹10,000/- 3582
2nd Prize ₹5,000/- 6471
3rd Prize ₹500/- 3223
4th Prize ₹300/- 9740
5th Prize ₹200/- 4319
6th Prize ₹100/-
0004 0085 0103 0126 0133 0157 0179 0189 0195 0244
0276 0277 0289 0311 0356 0364 0393 0401 0428 0431
0438 0439 0462 0465 0468 0506 0509 0541 0543 0596
0624 0625 0632 0653 0663 0668 0723 0727 0743 0762
0787 0809 0824 0877 0889 0893 0902 0930 0975 0985
1053 1063 1068 1069 1093 1108 1109 1116 1127 1131
1155 1159 1334 1440 1445 1462 1471 1538 1657 1661
1734 1790 1821 1843 1052 1064 1936 1970 1980 2066
2097 2105 2134 2227 2229 2264 2275 2290 2294 2333
2345 2362 2389 2455 2470 2476 2534 2547 2552 2560
2568 2570 2579 2581 2597 2663 2698 2731 2776 2804
2814 2946 2949 3011 3017 3090 3108 3148 3156 3191
3237 3254 3282 3292 3359 3414 3433 3458 3473 3505
3518 3561 3564 3598 3617 3622 3629 3696 3708 3710
3723 3726 3748 3795 3796 3818 3826 3833 3872 3874
3877 3892 3956 3974 3992 4002 4054 4088 4090 4091
4090 4104 4126 4234 4247 4253 4270 4276 4277 4326
4350 4407 4437 4445 4448 4460 4489 4495 4514 4515
4532 4547 4695 4727 4755 4759 4811 4812 4831 4871
4895 4806 4929 4940 4960 4968 4974 4996 5013 5016
5049 5061 5099 5105 5144 5182 5321 5357 5363 5368
5406 5423 5444 5462 5482 5495 5532 5575 5601 5602
5611 5672 5681 5682 5690 5696 5723 5732 5752 5014
5852 5877 5900 5985 6011 6047 6121 6128 6144 6157
6214 6232 6240 6245 6286 6370 6379 6385 6404 6406
6413 6420 6434 6450 6455 6458 6478 6498 6517 6611
6621 6644 6667 6694 6727 6735 6739 6746 6759 6787
6813 6864 6881 6891 6895 6926 6970 6994 7012 7047
7052 7076 7078 7080 7090 7094 7108 7129 7135 7197
7216 7276 7283 7300 7303 7320 7369 7415 7417 7425
7472 7479 7502 7521 7586 7622 7658 7697 7741 7785
7795 7873 7883 7886 7090 7919 8000 8017 6038 8085
8104 8111 8144 8194 8216 8217 8229 8233 8240 8242
8262 8295 8297 8335 8337 8373 8383 8444 8451 8463
8464 8538 8542 8554 8576 8585 8590 8640 8659 8713
8748 8796 8834 8844 8853 8919 8991 9023 9047 9061
9080 9147 9168 9176 9183 9231 9242 9277 9284 9325
9356 9393 9431 9464 9496 9533 9561 9581 9582 9639
9649 9670 9782 9788 9790 9860 9867 9871 9956 9968
ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES, GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

SIKKIM STATE LOTTERIES
Draw Time: 04:00 PM
LABHLAXMI GOLD MONDAY
Draw No:3 DrawDate on:31/01/22
1st Prize ₹10,000/- 1682
2nd Prize ₹5,040/- 8679
3rd Prize ₹508/- 3479
4th Prize ₹300/- 0588
5th Prize ₹200/- 6303
6th Prize ₹100/-
0013 0034 0046 0096 0108 0111 0175 0212 0226 0235
0245 0268 0272 0279 0304 0307 0309 0313 0326 0345
0347 0391 0410 0413 0443 0463 0464 0492 0510 0511
0548 0594 0611 0647 0692 0696 0697 0731 0737 0783
0825 0063 0885 0813 0947 0950 1052 1064 1148 1210
1212 1218 1259 1284 1286 1307 1372 1376 1394 1437
1448 1501 1510 1514 1525 1541 1546 1554 1560 1576
1596 1612 1626 1659 1668 1673 1733 1784 1787 1018
1853 1870 1886 1904 1923 1924 1929 1956 1967 1982
1987 1997 2005 2014 2017 2048 2059 2155 2174 2190
2192 2100 2243 2244 2252 2258 2278 2294 2335 2342
2344 2350 2378 2379 2475 2535 2536 2575 2614 2662
2664 2692 2697 2745 2761 2769 2790 2796 2877 2931
2975 2990 3006 3016 3175 3210 3219 3242 3250 3281
3288 3297 3323 3370 3393 3412 3426 3437 3459 3474
3498 3525 3605 3674 3693 3776 3780 3782 3790 3809
3832 3855 3863 3883 3009 3924 3970 3989 4021 4023
4069 4179 4206 4262 4200 4313 4344 4439 4444 4485
4508 4514 4520 4563 4607 4619 4622 4643 4697 4735
4759 4774 4818 4843 4844 4930 4964 5007 5016 5025
5039 5052 5088 5090 5095 5143 5163 5176 5206 5236
5268 5310 5312 5314 5317 5347 5360 5379 5418 5422
5480 5505 5553 5631 5652 5670 5682 5715 5718 5768
5885 5892 5936 5942 5960 6034 6041 6045 6105 6107
6143 6144 6175 6183 6221 6299 6385 6310 6319 6385
6388 6408 6416 6478 6564 6565 6586 6625 6736 6751
6758 6783 6815 6945 6954 6970 7003 7007 7031 7084
7126 7190 7196 7210 7225 7227 7230 7283 7292 7298
7301 7319 7325 7337 7355 7388 7406 7457 7545 7593
7598 7572 7676 7693 7709 7711 7775 7791 7796 7799
7800 7854 7860 7883 7961 7969 7971 7997 8007 8051
8069 8125 8130 8149 8103 8228 8247 8317 6321 8382
8402 8403 8420 8435 8553 8574 8641 8710 8715 8719
8729 8756 8785 8802 8870 8883 8926 8934 8936 8938
8944 8915 8051 8060 9063 9064 9070 9096 9107 9111
8118 8158 8166 8175 9194 9260 9313 9329 9332 9395
9400 9405 9415 9428 9448 9500 9503 9514 9554 9587
9646 9649 9650 9672 9679 9689 9697 9717 9720 9756
9759 9763 9773 9783 9791 9832 9862 9876 9897 9977
ISSUED BY : THE DIRECTOR, SIKKIM STATE LOTTERIES, GOVERNMENT OF SIKKIM DEORALI - 737102, SIKKIM.
For Results, please visit : www.sikkimlotteries.com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

संपादकीय पृष्ठ

प्रेग्नेंसी कोई बीमारी नहीं

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने चौतरफा विरोध के बीच आखिर अपना वह सर्कुलर वापस ले लिया जिसके मुताबिक तीन महीने या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को ड्यूटी जॉइन करने के अयोग्य करार दिया गया था। यह अच्छी बात है कि एसबीआई नेतृत्व को समय रहते अपनी गलती का अहसास हो गया और उसने अपने कदम वापस लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। पिछले 31 दिसंबर को जारी इस सर्कुलर में कहा गया था कि अगर प्रेग्नेंसी तीन महीने से ज्यादा की है तो कैंडिडेट को टेंपरेरी अनफिट माना जाएगा और उसे बच्चे की डिलिवरी के चार महीने बाद जॉइन करने की इजाजत होगी। इस सर्कुलर के जारी होने पर स्वाभाविक ही इसका तीखा विरोध होने लगा। न केवल बैंक कर्मचारी यूनियन इसके खिलाफ खुलकर सामने आए बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसके विरोध में मुहिम शुरू हो गई।

दिल्ली महिला आयोग ने इसे महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला और अवैध बताते हुए कहा कि यह सर्कुलर वापस लिया जाना चाहिए। विभिन्न दलों की महिला सांसदों ने भी अलग-अलग मंचों पर इसके खिलाफ आवाज उठाई। इन सबके मद्देनजर स्टेट बैंक ने इस सर्कुलर पर अमल रोकने की घोषणा जरूर कर दी है, फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि इस तरह का प्रतिगामी कदम बैंक ने कैसे और क्यों उठाया। याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में महिलाओं के लिए वर्किंग कंडिशंस अच्छी नहीं रही हैं। उदाहरण के लिए, 2009 तक स्टेट बैंक में इस बात पर जोर दिया जाता था कि नियुक्ति और प्रोमोशन के वक्त महिलाएं मेडिकल टेस्ट करवाकर सुनिश्चित करें कि वे प्रेग्नेंट हैं या नहीं। मासिक चक्र के विवरण के साथ उन्हें यह बताना होता था। बदलते सामाजिक माहौल में ऐसे प्रावधान भले अतीत की बात हो गए हों, लेकिन ताजा सर्कुलर जैसे उदाहरण बताते हैं कि पीछे की ओर ले जाने वाली शक्तियां आज भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार सतर्क रहने की जरूरत है।

इसी संदर्भ में यह सवाल भी उठता है कि क्या ताजा सर्कुलर को स्थगित करने मात्र से इस बहस को समाप्त मान लेना चाहिए? तीन महीने की प्रेग्नेंसी को अयोग्यता का पैमाना न मानने की घोषणा के बाद वह पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके मुताबिक छह महीने की प्रेग्नेंसी को अयोग्यता का पैमाना माना जाता है। सवाल यह है कि क्या प्रेग्नेंसी कोई बीमारी या अपराध है?

अगर नहीं तो उसे किसी कर्मचारी को अनफिट करार देने का आधार कैसे बनाया जा सकता है? प्रेग्नेंसी के दौरान महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा और सहूलियत उपलब्ध कराने की बात तो समझ में आती है, लेकिन इस आधार पर उन्हें अनफिट करार देना उनके साथ भेदभाव का ही एक रूप है। इसे समझते हुए तमाम संस्थानों में ऐसे प्रावधान बदले जाने की जरूरत है।

पोस्टकार्ड और संभावनाएं

अनिता करनाल

जब आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक खोजपूर्ण और रचनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आप विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, यहां तक कि किसी अनजान भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं व भविष्यवाणी करते हैं, तो आपकी सोच को भविष्य की सोच कहा जा सकता है। स्कूली शिक्षा प्रणाली, जिसकी आलोचना कभी-कभी रटने पर आधारित प्रणाली के रूप में की जाती है, के छात्रों से संभवत: वर्तमान से आगे तक देखने और अनजान भविष्य या अनदेखे अतीत पर अपने विचार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। परन्तु, देश के बच्चों ने ऐसी सभी धारणाओं को गलत साबित किया है।

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में, तीन विभागों - स्कूल शिक्षा, डाक और संस्कृति- के द्वारा एक संयुक्त पहल के तहत देश के कोने-कोने से कक्षा 4 से 12 तक के बच्चों को, दो विषयों- 'हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक' और '2047 के भारत के लिए मेरा विज़न' - पर माननीय प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

एक अनुमान के मुताबिक, भारत में लगभग 50 करोड़ पोस्टकार्ड प्रतिवर्ष लिखे जाते हैं। इनमें से एक करोड़ से अधिक पोस्टकार्ड इस साल दिसंबर-जनवरी में बच्चों द्वारा एक ही पते पर भेजे गए थे- प्रधानमंत्री के पते पर! बच्चों के इस अपार उत्साह के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया और कुछ बच्चों के पोस्टकार्ड को पढ़कर सुनाते हुए उनके अर्थ व मूलभाव पर चर्चा की।

मैं भी यहाँ पर कुछ उन मुख्य बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, जिन्हें प्रधानमंत्री ने बच्चों की मन की बात का नाम दिया है। बच्चों ने हमारी आजादी के गुमनाम नायकों के योगदान और बलिदान के बारे में बड़े गर्व के साथ विस्तार से चर्चा की है। एक बच्चे ने लिखा है,एक भारतीय क्रांतिकारी,मातंगिनी हाजरा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए वे कई महिलाओं की प्रेरणा बनीं। एक अन्य छात्र कि हम धीरे-धीरे अपने नायकों जैसे तारा रानी, तिरोट सिंह, दुर्गाबाई देशमुख आदि को भूल रहे हैं, इसलिए हमें इन 'गुमनाम नायकों' को याद करने के लिए हर साल राष्ट्र का एक दिन समर्पित करना चाहिए। एक छात्रा ने अपना पूरा पोस्टकार्ड आजाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल को समर्पित किया है। दुर्गाबाई देशमुख, बिरसा मुंडा, पिंगली वेंकैया, नानी बाला देवी, कुंवर प्रताप सिंह बारहठ, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, मदनलाल ढींगरा, मुनिदेव त्यागी, विश्वनाथ दास, भीकाजी कामा और हीराजी गोमाजी पाटिल के बारे में कई बच्चों ने लिखा है। एक छात्र ने भीमा बाई होल्कर की भूमिका को विस्तार से बताया है और कहा है कि वे इस बात की जीती-जागती परिभाषा थीं कि एक व्यक्ति अपने विचार के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन उसका विचार उनकी मृत्यु के बाद एक हजार लोगों में अवतरित होगा।

कुछ बच्चों ने बाल नायकों के बारे में भी लिखा है, जैसे सूरत, गुजरात के नायक शिरीष कुमार का बाल बलिदान और वीर कनकलता बरुआ, जिन्हें बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है और जिनकी 17 साल की उम्र में स्थानीय पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पच्चीस साल बाद देश के स्वरूप की परिकल्पना करने में सक्षम होना कोई आसान काम नहीं है। हम वयस्कों के लिए भी भविष्य की परिकल्पना करना कठिन हो जाता है, लेकिन इन बच्चों ने भारत 2047 का एक स्पष्ट विज़न प्रस्तुत किया है। आठवीं कक्षा का एक छात्र भारत को 'पूरी तरह से साक्षर, सामंजस्यपूर्ण और आत्मनिर्भर' देश के रूप में देखता है। भारत के लिए मेरा दृष्टिकोण प्रकृति और विरासत से भरा है। हर जगह मानवता और प्रेम का बोलबाला है। मेरा देश रहने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी- धरती पर स्वर्ग।' पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा 'गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, अस्वस्थता, आतंकवाद, लैंगिक भेदभाव और खाद्यान्न की कमी से मुक्त भारत' की मार्मिक परिकल्पना प्रस्तुत करता है।

कई बच्चों ने व्यक्त किया है कि वे मेक इन इंडिया पहल से बहुत प्रभावित हैं। नौवीं कक्षा की एक छात्रा लिखती है- 'मेक इन इंडिया के प्रतीक ने मेरे हृदय में एक गर्व की भावना भर दी है। मैं भारत माँ के सभी बेटों का आह्वान करती हूं कि वे आगे आएं और उनके लिए कार्य करें।' एक प्राथमिक स्कूल के बच्चे का कहना है, 'हम एक बहुत शक्तिशाली, फिर भी पूरी तरह एकजुट देश को देखेंगे।' सातवीं कक्षा के एक छात्र ने लिखा है कि 2047 में मेरे देश को केवल पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना चाहिए; किसानों को अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए और महिलाओं का हर जगह सम्मान होना चाहिए। एक बालिका लिखती है, 'हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना है, जिसके पास पर्याप्त खाद्यान्न हों और राष्ट्र कार्बन-मुक्त, पर्यावरण-अनुकूल और ख़लास्टिक-मुक्त हो।' बच्चों ने एक ऐसे भारत के बारे में भी लिखा है, जो संगीत और नृत्य की अपनी विरासत को फिर से हासिल करेगा।

कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक स्वभाव और परिकल्पना को वास्तव में विस्तार दिया है। बच्चों ने अंतरिक्ष के लिए उच्च क्षमता विकसित करने, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने, चंद्रयान-2 और चंद्रमा पर एक शोध केंद्र तथा मंगल ग्रह को मनुष्यों के रहने योग्य बनाने के बारे में लिखा है। कुछ बच्चों ने शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल करने और दुनिया का सबसे साक्षर देश बनने के बारे में लिखा है। एक बच्चे ने उम्मीद जताई है कि 'योग, आयुर्वेद और कृषि स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएंगे।' कई बच्चों ने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की है, जहां महिलाएं सुरक्षित और 'पुरुषों के समान' होंगी, और हमारा देश एक स्वच्छ एवं हरा-भरा देश होगा, जहां 'प्रत्येक नागरिक केवल कूड़ेदान में ही कचरा फेंकेंगे।' बच्चों ने एक ऐसे देश के बारे में भी लिखा है, जहां पानी की एक-एक बूंद का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा।

जिस तरीके से हम अपने अतीत से सीखते हैं और वर्तमान में हम जिन विकल्पों का चयन करते हैं, उनसे ही हमारे सपनों के भविष्य का निर्माण होगा। इन बच्चों ने हमें विश्वास दिलाया है कि हमारा भविष्य वास्तव में सुरक्षित हाथों में है। **(लेखक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सचिव है)**

देश का बजट और बेरोजगारी

पत्रलेखा चटर्जी

अगले हफ्ते जब केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, तब उम्मीद है कि बढ़ते रोजगार संकट और बढ़ती गरीबी की परस्पर जुड़ी चुनौती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी उम्मीद है कि आने वाला बजट बढ़ती आर्थिक असमानताओं को दूर करेगा। सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के पास कोई पारिवारिक संपत्ति या सामाजिक सुरक्षा नहीं है। केंद्रीय बजट में ऐसे कमजोर परिवारों की सहायता के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने चाहिए।

शहरी गरीबों के लिए मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार की पहल हो सकती है और अर्थव्यवस्था में सुधार होने तक मुफ्त खाद्य वितरण को जारी रखा जा सकता है। चूंकि रोजगार संभवत: सबसे बड़ी चिंता है, और जनसंख्या विस्फोट के चलते देश का जनसांख्यिकीय लाभांश खतरे में है, क्योंकि रोजगार चाहने वाले युवा दिन-ब-दिन हताश होते जा रहे हैं, इसलिए हमें सार्वजनिक खर्च में तेज वृद्धि और कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2021 के दौरान कई बड़ी पहल की, जिनमें ई-श्रम पोर्टल का उद्घाटन, ईपीएफओ से जुड़ी आत्मनिर्भर भारत योजना, गुरुग्राम (मानेसर), शाहजहांपुर, हरिद्वार, विशाखापट्टनम, मेरठ और तिनसुकिया (असम) में नए ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना आदि शामिल हैं। दिसंबर, 2021 का एक आधिकारिक बयान बताता है कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 30 दिसंबर, 2020 को ईपीएफओ से जुड़ी आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) से संबंधित अधिसूचना जारी की।

एबीआरवाई का उद्देश्य अनौपचारिक रोजगार को औपचारिक रूप देने में मदद करना और कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। जहां तक रोजगार सृजन का संबंध है, हमें लगातार इस पर नजर रखने की जरूरत है कि मौजूदा योजनाएं किस तरह आगे बढ़ रही हैं और उन लाखों लोगों को ऊपर उठाने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है, जो अब भी एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।

प्रो जयती घोष जैसे विकास अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन (ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विस्तार और राष्ट्रीय स्तर पर शहरी रोजगार कार्यक्रम के निर्माण के माध्यम से) पहले से कहीं अधिक जरूरी आवश्यकता है।

मनरेगा शहरी और ग्रामीण भारत, दोनों में पहले से ही निराश्रित और नए गरीबों के लिए एक जीवन रेखा रही है। लेकिन इस योजना को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के तहत अब भी औसतन 50 दिन से कम काम दिए जाते हैं। उनके मुताबिक, मनरेगा में पूरे 100 दिनों के लिए बजटीय प्रावधान करना जरूरी है।

छह साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना में दिसंबर, 2021 तक 40.35 करोड़ खाते में कुल 13 खरब रुपये से ज्यादा की राशि जमा थी। लेकिन लोगों को उन बैंक खातों में धन के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता है। समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, तभी वह अधिक खपत को बढ़ावा देगा और इसका सकारात्मक असर होगा।

यह संभावित रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के पुनरुद्धार को गति दे सकता है, जो मांग की कमी के कारण ठप हैं या खत्म हो रहे हैं। इससे आर्थिक पुनरुद्धार को भी बढ़ावा मिलेगा। महामारी के तीसरे वर्ष में, नौकरी छूटना, कम कमाई और भविष्य के बारे में अनिश्चितता भारतीयों के लिए विनाशकारी है। युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है और कभी-कभी सड़कों पर फैल रहा है, क्योंकि नौकरी तलाशने वाले बहुत हैं और नौकरियां कम हैं।

यह कोई रहस्य नहीं है कि महामारी से पहले भी भारत में नौकरी का गंभीर संकट था। वर्ष 2017-18 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के पीएलएफएस सर्वे ने रोजगार में थोड़ा सुधार दिखाया, पर जो कुछ भी हासिल किया गया था, उसे महामारी की दो लहरों और फिर ओमिक्रॉन ने मिटा दिया है। महामारी एवं उससे जुड़े प्रतिबंधों ने लोगों की कमाई को बुरी तरह प्रभावित किया। अनेक लोग महामारी के कारण भारी कर्ज में डूबे हैं और उनकी बचत भी खत्म हो गई।

आने वाले हफ्तों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी बेरोजगारी का संकट गहराया हुआ है। महामारी के दौरान असमानता बढ़ी है।

पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकनॉमी द्वारा अप्रैल से अक्टूबर, 2021 के बीच कराए गए सर्वे के मुताबिक, सबसे गरीब 20 फीसदी भारतीय परिवारों की वार्षिक आय 1995 से बढ़ रही थी, पर महामारी वर्ष 2020-21 में 2015-16 के स्तर से 53 फीसदी कम हो गई। इन्हीं पांच वर्ष की अवधि के दौरान सबसे अमीर 20 फीसदी भारतीयों की वार्षिक घरेलू आय में 39 फीसदी की वृद्धि देखी गई। जाहिर है, अरबपतियों की बढ़ती संपत्ति कम नहीं हुई।

शहरी गरीब विशेष रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि उनके पास वह सामाजिक समर्थन नहीं होता, जो उनके ग्रामीण समकक्षों के पास होता है। गांव में लोगों के सिर पर छत होती है, भले ही वह फूस की हो और जमीन का एक छोटा-सा भूखंड होता है, जहां कम से कम वह थोड़ी देर के लिए टिक सकता है। भले ही कम मजदूरी मिले, पर खेतों में काम मिल जाता है। लेकिन शहरों में चाहे महामारी हो या नहीं, मकान मालिक घर का किराया मांगते हैं, खाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

मार्च, 2021 में ख़यू रिसर्च सेंटर के विश्लेषण से पता चला कि महामारी की पहली लहर ने 7.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया और मध्यवर्ग से 3.2 करोड़ लोग बाहर निकल गए। महामारी की दूसरी लहर ने और अधिक लोगों को गरीबी में धकेला, क्योंकि इसने कई गुना ज्यादा लोगों को मारा और संक्रमित किया। महामारी ने लाखों लोगों को मौत, इलाज खर्च, नौकरी एवं व्यवसाय के नुकसान के कारण गरीबी के गड्ढे में धकेला। ऐसे में, आने वाले बजट में रोजगार सृजन राजनीतिक प्राथमिकता में होना चाहिए। और यह अपने आप नहीं होगा। इसके लिए सरकार से बड़े प्रोत्साहन की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा जरूरी लोगों में उम्मीद जगाने की आवश्यकता है।

बेरोजगार युवा और सरकारी तंत्र

विनीत नारायण

पिछले दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश में युवकों द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (आरआरबी-एनटीपीसी) परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर उग्र प्रदर्शन किए गए।

सरकार ने रेल रोकने से लेकर रेल में आग लगाने जैसे प्रदर्शन की न सिर्फ उनदा की है, बल्कि छात्रों पर बर्बरता से लाठियां भी चलाई। सोशल मीडिया पर इस लाठीचार्ज के वीडियो भी खूब वायरल हुए। इस बवाल के बाद से विपक्ष इस मामले को लेकर एकजुट होता दिखाई दिया और न सिफर्. छात्रों के समर्थन में उतरा, बल्कि उसनके केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला।

इसी दौरान बिहार के एक छात्र ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। चुनावों के मौसम में इन सवालों से केंद्र सरकार को काफी दिक्कत आ सकती है। आज के दौर में अगर मेनस्ट्रीम मीडिया किन्हीं कारणों से ऐसे सवालों को जनता तक नहीं पहुंचाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जनता तक वह सवाल पहुंच नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर यह इंटरव्यू काफी देखा जा रहा है।

इस वीडियो में छात्र रेल मंत्री अनिी वैष्णव के एक बयान का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि 1.27 करोड़ छात्रों ने भर्ती के लिए आवेदन दिए हैं, तो परीक्षा कैसे हो सकती है? इंटरव्यू के दौरान छात्र ने एक ऐसी बात कह दी जो सभी युवकों को छू गई। उस छात्र ने कहा, परीक्षा की तैयारी के दिनों में कभी-कभी ऐसा भी हुआ जब घर से पैसा समय पे नहीं आता था तो हम लोग गर्म पानी पी कर सो जाते थे। अगर छात्र इतनी कठिन परिस्थितियों में रह कर नौकरी पाने की उम्मीद में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और जब परीक्षा में धांधली की खबर मिलती है तो छात्र क्या करें? कैसे अपने ग़ुस्से को रोकें? सरकार को क्यों न कोसें? छात्रों के उग्र होने के सवाल पर छात्रों ने बताया कि 14 जनवरी को आए नतीजों का 10 दिनों तक विभिन्न डिजिटल माध्यमों से लगभग एक करोड़ बार विरोध किया गया। जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं बचा तो डिजिटल विरोध के हैश-टैग को बैन कर दिया गया। इसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे और निहत्थे छात्रों पर सरकारी तंत्र ने लाठियां भांजीं। किसान आंदोलन के बाद सरकार को सोचना चाहिए कि छात्रों की मांग को देखते हुए उनके प्रतिनिधि से बात कर कोई हाल जरूर निकाला जा सकता था। अगर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की भी उम्मीद नहीं होगी तो हार कर उन्हें निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा और निजी क्षेत्र की मनमानी का सामना करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया के देशों में अनौपचारिक रोजगार के मामले में भारत सबसे ऊपर है। जिसका मतलब हुआ कि हमारे देश में करोड़ों मजदूर कम मजदूरी पर बेहद मुश्किल हालात में काम करने पर मजबूर हैं, जहां इन्हें अपने बुनियादी हक भी प्राप्त नहीं हैं। इन्हें नौकरी देने वाले जब चाहे रखें, जब चाहें निकाल दें क्योंकि इनका ट्रेड यूनियनों में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार भारत में 53.5 करोड़ मजदूरों में से 39.8 करोड़ मजदूर अत्यंत दयनीय अवस्था में काम करते हैं, जिनकी दैनिक आमदनी 200 रुपये से भी कम होती है। इसलिए मोदी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, शहरों में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं? क्योंकि पिछले सात वर्षों में बेरोजगारी का फीसदी लगातार बढ़ता गया है; और दूसरा, शहरी मजदूरों की आमदनी कैसे बढ़ाएं, जिससे उन्हें अमानवीय स्थिति से बाहर निकाला जा सके।

इसके लिए तीन काम करने होंगे। भारत में शहरीकरण का विस्तार देखते हुए शहरी रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय करके नीतियां बनानी होंगी। इससे यह लाभ भी होगा कि शहरीकरण से जो बेतरतीब विकास और गंदी बस्तियों का सृजन होता है, उसको रोका जा सकेगा। इसके लिए स्थानीय शासन को अधिक संसाधन देने होंगे। दूसरा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने वाली विकासात्मक नीतियां लागू करनी होंगी। तीसरा, शहरी मूलभूत ढांचे पर ध्यान देना होगा जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुधरे। चौथा, देखा यह गया है कि विकास के लिए आवंटित धन का लाभ शहरी मजदूरों तक कभी नहीं पहुंच पाता और ऊपर के लोगों में अटक कर रह जाता है। इसलिए नगर पालिकाओं में विकास के नाम पर खरीदी जा रही भारी मशीनों की जगह अगर मानव श्रम आधारित शहरीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा तो शहरों में रोजगार बढ़ेगा। पांचवा, शहरी रोजगार योजनाओं का स्वास्थ्य और सफाई जैसे क्षेत्र में तेजी से विकास करके बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आज यह हालत नहीं है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे सके। अगर होती तो वे गांव छोड़ कर शहर नहीं गए होते।

मौजूदा हालात में यह सोचना कि पढ़े-लिखे युवाओं के लिए एक ऐसी योजना लानी पड़ेगी जिससे इनको भी रोजगार मिल जाए। पर ऐसा करने से करोड़ों बेरोजगारों का एक छोटा सा अंश ही संभल पाएगा। जबकि बेरोजगारों में ज्यादा तादाद उन नौजवानों की है, जो आज देश में बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार हैं। इससे उनका आक्रोश बढ़ चुका है। कुछ वर्ष पहले सोशल मीडिया पर एक व्यापक अभियान चला कर बेरोजगार नौजवानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस को ही बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया था।

उस समय इसी कॉलम में मैंने कहा था कि यह खतरनाक शुरुआत है, जिसे केवल वायदों से नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षित रोजगार उपलब्ध कराकर ही रोका जा सकता है। नरेन्द्र मोदी ने 2014 के अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रति वर्ष 2 करोड़ नये रोजगार सृजन का अपना वादा निभाया होता तो आज ये हालात पैदा न होते जिसमें देश के रेल मंत्री को ही मानना पड़ा कि पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में ज्यादा फार्म भरे गए।

उपहार का ऐसा लेनदेन ना ही करो तो बेहतर

बेबी की दोस्त अलका ने कान में जो टॉप्स पहने थे उसमें एक सफेद मोती चिपका था। वो बड़े जतन से उसे संभाल कर पहने थी। कहीं गिर न जाएं। बेबी ने पूछा ऐसे क्यों कर रही ? अलका ने बड़े प्यार और गर्व से बताया कि मेरी भाभी नेपाल से ये टॉप्स सच्चे मोती के लाई है। बहुत महंगे हैं। सुन कर बेबी जोर-जोर से हंसने लगी। बोली ये टॉप्स आड़ा बाजार के हैं। ठेलों में दस-दस रूपये में मिल रहे हैं। तेरी भाभी जब खरीद रही थी तब मैं भी वहीं खड़ी थी। ये देख मैंने भी लिये। अलका का मुंह उतर गया। शर्मिंदगी होने लगी खुद पर। सोचने लगी उसकी भाभी ने ऐसा उसके साथ क्यों किया? पर कोई कारण उसे समझ ही नहीं आया। एक बार लक्ष्मी को डॉक्टर ने हवा पानी बदलने की सलाह दी। ज्यादा दूर जाने की बजाय उसके घर के लोगों ने उन्हें पचमढ़ी जाने की सलाह दी। उस की बड़ी बहन भी भोपाल ही रहती थी तो उसे भी ठीक लगा। वहां एक रात रुकने का इरादा किया। अगली सुबह पचमढ़ी, फिर वापिस इंदौर लौट आने का कार्यक्रम तय हो गया। अपनी नन्ही सी बेटी के साथ निजी वाहन में चल पड़े। शादी के बाद पहली बार बहन के घर जा रहे थे। बड़े खुश थे। रात को पहुंच कर खाना खाया और सुबह निकलने की तैयारी की। बहन हाथ में कुछ पैकेट लिए आई। कंकू लगाया और पैकेट थमा दिए। लक्ष्मी ने ऐसे के ऐसे ही बेग में रख लिए। तय कार्यक्रम से पचमढ़ी टूर पूरा किया, घर लौट आये। सभी के सामने बड़ी बहन के दिए गिफ्ट खोले। उसमें लक्ष्मी की सालभर की गुडिया का छोटा सा गर्मियों में पहनने सा दो बद्दी वाला लेडिस रुमाल के जितने कपड़े वाला फ्राक/झबला, पति के लिए खादी का कुरता, लक्ष्मी के लिए सलवार कुर्ता था।

यहां तक तो ठीक है पर जब देखा तो उसमें प्राइज टेग लगे थे। उनमें सभी की कीमत लिखीं थी। जानते हैं उनमें क्या कलाकारी थी? उसने उन सभी में अंक बढा दिए थे। किसी में आगे जीरो किसी में पीछे संख्या। साथ ही जिस पेन से किये उनकी स्याही का रंग व लिखावट में भारी अंतर था। वो भूल गई की सभी अन्न खाते हैं। लक्ष्मी के ससुर उसी वक्त घर के सामने ही खादी ग्रामोद्योग की दुकान गए और वहां से उनकी असल कीमत जानी। कितनी हद है यह तो। आपने अपनी मर्जी से दिए थे न, तो फिर ऐसी नालायकी करने की क्या जरुरत आ पड़ी। उसकी बहन का पति बैंक मनेजर, वो खुद सेंट्रल गवरमेंट की अच्छी खासी नौकरी में थी। शायद लक्ष्मी व उसके पति को उसने अपनी झूठी शान की छाप छोड़ने के लिए ऐसी बेवकूफाना हरकत की हो। पर ये निरी परम मूर्खता ही थी। जिससे लक्ष्मी को तो लज्जित होना ही पड़ा, संबंधों में भी आजन्म खटास पैदा हो गई। लक्ष्मी ने तुरंत यह कह कर सब वापिस भेज दिए कि हम इतने महंगे कपड़े नहीं पहनते। उसकी बहन को समझ तो सब आ गया था पर जिसकी आंखों और अक्ल में बेशर्मी की पट्टी चढ़ी होती है उसे कुछ भी दिखाई जो नहीं देता। और ऐसे लोग ऐसी हरकतों से बाज भी नहीं आते। कभी 'म्यांमार' की साड़ी पहनी है आपने? साडियां पहनने वाला भारत देश अब म्यांमार से साड़ी बुलवाएगा। सोच कर ही तरस आता है ऐसे लोगों पर। निधि के मकान का वास्तु हुआ था। उसकी मामी ने एक साड़ी उसे यह कहकर ओढाई की तेरे मामा इसे म्यांमार से तेरे लिए लाये हैं। हरे रंग की मोटे रेग्जिन से कपड़े वाली साड़ी का वे जोर जोर से सबके बीच 'इम्पोर्टेड है' कह कर बखान रहे थे। निधि पढी-लिखी डॉक्टरेट थी। पर चुप थी।

उसकी भाभी ने बताया की यह साड़ी मामी को उनके पीहर से उनकी भाभी ने दी थी जो इन्हें पसंद नहीं आई। आनी भी नहीं थी। हम भारतवासीयों को 'म्यांमार' की साड़ी कैसे पसंद ? बस उन्होंने 'टिका' दी निधि को। अकेले में निधि ने मामी से पूछ ही लिया कि 'मामी विदेशों में वो भी म्यांमार जैसी जगह साडियां कैसे? मैंने तो कहीं पढ़ा-सुना नहीं। यदि हैं तो गईं भारत से ही होंगी न? वैसे ऐसी साड़ी मैंने आपके पीहर में किसी के पास देखी है।'

बस मामी को काटो तो खून नहीं। उनका दांव फेल जो हो गया था। आज की भाषा में 'एक्सपोज' होना कहते हैं इसे। क्यों करते हैं लोग ऐसा समझ से ही परे है। इन सभी परिस्थितियों को आपको खुद ही अपनी बुद्धि व विवेक से परिस्थितियों के मद्देनजर निपटना व सुलझाना होता है। इस बीमारी का कोई परमानेंट ईलाज आज तक नहीं मिल पाया है। 'जैसे को तैसा' वाला फार्मूला चला सकें तो लगाइए। वरना भुगतें । सहन करें। या 'मुंह फट' हो जाइए। क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके, हमारे, हम सभी के साथ कभी न कभी घटता है। यदि नहीं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।

ये सारे लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। यहीं होते हैं हमारे साथ, हमारे आस-पास। कुछ अपने कुछ पराये जिन्हें दूसरों के साथ ऐसा करने की गन्दी लत पड़ी होती है। यह तो कुछ छोटे से, जरा से ही उदाहरण मैंने पेश किए हैं। इनके आलावा भी कई और कई प्रकार के , कई मौकों पर गिफ्ट-गेम इज्जत का फलूदा करते-कराते खेले जाते हैं और खेले जाते रहेंगे। कारण कई हो सकते है क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन का यही है.

सर्दियों के मौसम में कपड़ों से नहीं आएगी दुर्गन्ध

अपनाएं ये आसान टिप्स

सर्दियों के मौसम में हवा में नमी होने की वजह तो कई बार गलत तरीके से कपड़ों की सफाई करने से तो कभी गलत तरीके से कपड़े को रखने से बदबू आने लगती है। अगर कपड़े की सफाई से लेकर उसे रख-रखाव पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो किसी भी मौसम में कपड़ों से बदबू नहीं आएगी।

यार, 'आज ही तो इसे अलमारी से निकाला है पहनने के लिए और पता नहीं इस ड्रेस से अजीब किस्म की दुर्गंध आ रही है'। कुछ दिन पहले भी स्वेटर और कोट निकाला था पहनने के लिए उससे भी ठीक ऐसी ही दुर्गन्ध आ रही थी'। शायद, आपने ने भी किसी न किसी से ये शब्द जरूर सुना होगा कि गर्मी के मौसम तो नहीं लेकिन, सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों से लेकर अन्य कपड़ों से एक अजीब किस्म की बदबू आती है। ऐसे में अगर अन्य कपड़ों से लेकर सर्दियों के कपड़ों से कुछ अजीब किस्म की बदबू आती है, तो फिर आपको इस लेख को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि, इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप किसी भी कपड़े से दुर्गन्ध को आसानी से दूर कर सकती हैं, तो आइए जानते हैं।

गुलाब जल का इस्तेमाल करें

जी हां, सर्दियों में कपड़ों से किसी भी दुर्गन्ध को दूर करने के लिए जुलाब जल एक बेस्ट उपाय हो सकता है। इसके इस्तेमाल से ऊनी पकड़ों से लेकर अन्य कपड़ों से भी दुर्गन्ध आसानी से गायब हो सकती है। इसके लिए फ्रेश कपड़ों पर छिड़काव करने की जरूरत नहीं बल्कि, सफाई के दौरान इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके लिए फॉलो करें आसान स्टेप्स-

- सबसे पहले दो से तीन लीटर पानी में तीन से चार चम्मच नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर को डालकर एक मिश्रण तैयार कर लीजिए।
- अब आप इस घोल में कपड़े को डालकर कुछ देर बाद अच्छे से साफ कर लें।
- इसके बाद तीन से चार लीटर पानी में साफ किए कपड़े को अच्छे से धो लें।
- फिर से एक से दो लीटर पानी में एक से दो चम्मच गुलाब जल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इस पानी में साफ किए कपड़े को डालकर कुछ देर ले लिए छोड़ दें।
- लगभग 5 मिनट बाद पानी में से कपड़े को निकालकर अच्छे से पानी को निचोड़ लें और धूप में रख दें।
- ध्यान रहे जब तक कपड़ा एकदम ठीक से सुख न जाए तब तक उसे अलमारी में न रखें।
- इससे कपड़े में से कभी भी बदबू नहीं आएगी। कपड़ा हमेशा सुगंन्धित रहेगा।

ऊनी कपड़ों से ऐसे करें दुर्गन्ध को दूर

सर्दी के मौसम अगर सबसे अधिक किसी कपड़े से अजीब किस्म की बदबू आती है, तो वो है ऊनी के कपड़े। कई बार गलत तरीके से स्टोर करने या फिर नमी वाली जगह रखने पर इससे दुर्गन्ध आने लगती है। कई बार ठीक से सफाई न करने या फिर गलत डिटर्जेंट के इस्तेमाल करने से भी बदबू आने लगती है। ऐसे में ऊनी कपड़ों से किसी भी बदबू को दूर करने के लिए आप लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स-

- सबसे पहले तीन से चार लीटर पानी में इजी लिक्विड डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।
- अब इस घोल में स्वेटर और अन्य ऊनी के कपड़ों को डालकर लगभग 10 मिनट के बाद अच्छे से साफ कर लें।
- अब इन कपड़ों को फ्रेश पानी में अच्छे से साफ कर लें।
- इसके बाद दो से तीन लीटर पानी में एक चम्मच लैवेंडर ऑयल अच्छे से मिक्स कर लें और इस मिश्रण में साफ ऊनी के कपड़े डालकर निकाल लें और अच्छे को पानी निचोड़ लें। इसके बाद इसे धूप में अच्छे से सुखने के लिए रख दें। इससे ऊनी कपड़ों से कभी भी दुर्गन्ध नहीं आएगी।

इन टिप्स को भी आप कर सकती हैं फॉलो

सर्दियों के मौसम में कपड़ों से दुर्गन्ध को दूर करने के लिए आप सिर्फ जुलाब जल या लैवेंडर ऑयल का ही इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं बल्कि, इसके अलावा कई चीजें हैं जिसके इस्तेमाल से आप कपड़ों से दुर्गन्ध को दूर कर सकती हैं। सफाई के दौरान आप एक से दो चम्मच सिरका, चन्दन के तेल के अलावा आप अन्य किसी सेंटेड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान

- सर्दियों के मौसम में किसी भी कपड़े को नमी वाली जगह रखने से बचें।
- ऊनी कपड़े या अन्य कपड़ों को कुछ समय के लिए धूप में जरूर रखें।
- वाशिंग मशीन में कपड़ों को साफ करते समय आप उसमें गुलाब जल, जैस्मिन ऑयल या फिर अन्य सेंटेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं।
- अलमारी या अन्य जगह रखें कपड़ों पर आप सुगंधित स्प्रे का छिड़काव कर सकती हैं या सुगंधित स्प्रे से कॉटन को अच्छे से भिगोकर अलमारी में भी रख सकती हैं।
- अगर कपड़े में हल्का भी नमी है तो उसे फोल्ड करके अलमारी में न रखें बल्कि उसे हवा के नीचे रखें।
- सर्दियों के मौसम में ऊनी और अन्य कपड़ों को अलग-अलग रखने की कोशिश करें।

ड्राइंग रूम की सजावट में रखें इन बातों का ध्यान

वास्तु शास्त्र में कोई भी भवन खरीदते या उसकी सजावट करते समय कई बातों का ध्यान देना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि घर का मुख्य कक्ष, बैठक कहें या ड्राइंग रूम वह जगह है, जहां हम अपने परिवारजनों और कुछ खास मित्रों के साथ कुछ क्षण आनंद से गुजारना चाहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसी अन्य मित्र के घर के ड्राइंग रूम में जाने पर हमें अजीब-सा भारीपन महसूस होता है, जबकि दूसरे मित्र के ड्राइंग रूम में हल्कापन लगता है। आइए जानें कैसी हो ड्राइंग रूम की सजावट

- ड्राइंग रूम में प्रकाश, घड़ी, कैलेंडर और तस्वीरों के चयन में भी सावधानी रखी जानी चाहिए।
- विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि वे तनाव बढ़ाने वाले न हों। जहां तक हो सके प्रयास किया जाए कि अध्ययन कक्ष, बेडरूम तथा अन्य कक्षों के भीतरी भाग बैठक से नजर न आएं।
- बैठक से अध्ययन कक्ष की मेज तथा काम के अन्य उपकरण दिखाई देने से भी बैठक में तनाव बढ़ता है।
- वास्तु और फेंगशुई के प्रचार के बाद से वास्तव में लोग अपने मकान के निर्माण या बना-बनाया फ्लेट खरीदते समय वास्तु आदि पर ध्यान तो देने लगे हैं, किंतु मकान में प्रवेश करने के बाद उसकी सजावट करते हुए वास्तु और फेंगशुई को प्राय: भूल जाते हैं।
- जबकि सोफा, टेबल आदि फर्नीचर का आकार, दीवारों की सजावट, चित्रों की विषय वस्तु, प्रकाश व्यवस्था आदि सब मिलकर वास्तु का प्रभाव तय करते हैं।
- दरवाजे के ठीक ऊपर लगा कैलेंडर या बंद पड़ी घड़ी से भी बैठक की अच्छी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है।
- फर्नीचर खरीदी करने का तरीका अक्सर यह रहता है कि दुकान पर गए, जो पसंद आया, उठा लाए। फिर चाहे वह बैठक के अनुपात में हो, रंगों आदि से मेल खाता हो या न हो।
- ड्राइंग रूम के आकार के अनुपात से बड़ा सोफा अच्छी ऊर्जा अर्थात ची को प्रभावित करता है और भारी सोफा गृहस्वामी के अलावा आगंतुकों के लिए भी भारीपन की रचना करता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि ड्राइंग रूम के लिए फर्नीचर का चुनाव करते हुए उनके आकार का ध्यान जरूर रखें।

अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वह पढ़ाई से जी चुरा रहा है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है तो आप नीचे दिए गए टिप्स के अनुसार बच्चे के कमरे में वास्तु परिवर्तन करेंगे तो निश्चित ही वह मन लगाकर पढ़ेगा तथा उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा।

अगर ऐसा होगा आपके बच्चे का रूम तो पढ़ाई में होगा सर्वश्रेष्ठ

- बच्चों के कमरे में पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो कि दिन में पढ़ते समय उन्हें कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता ही न हो।
- जहां तक संभव हो सके, बच्चों के कमरे की उत्तर दिशा बिलकुल खाली रखना चाहिए।
- उनके किताबों की रैक नैऋत्य कोण में स्थित हो सकती है।
- खिड़की, एसी तथा कूलर उत्तर दिशा की ओर हो।
- बच्चों के कमरे में स्थित चित्र एवं पेंटिंग्स की स्थिति उनके विचारों को प्रभावित करती है इसलिए हिंसात्मक, फूहड़ एवं भड़काऊ पेंटिंग्स एवं चित्र बच्चों के कमरे में कभी नहीं होना चाहिए।
- महापुरुषों के चित्र, पालतू जानवरों के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य वाले चित्र तथा पेंटिंग्स बच्चों के कमरे में हो सकती हैं।
- भगवान गणेश तथा सरस्वती जी का चित्र कमरे के पूर्वी भाग की ओर होना चाहिए। इन दोनों की देवी-देवताओं को बुद्धिदाता माना जाता है अत: सौम्य मुद्रा में श्री गणेश तथा सरस्वती की पेंटिंग या चित्र बच्चों के कमरे में अवश्य लगाएं।
- आपका बच्चा जिस क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहा है, उस करियर में उच्च सफलता प्राप्त व्यक्तियों के चित्र अथवा पेंटिंग्स भी आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं।
- यदि बच्चा छोटा हो, तो कार्टून आदि की पेंटिंग्स लगाई जा सकती है।
- बच्चों के कमरे में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में होने वाला शोरगुल उन्हें बिलकुल बाधित न करे अत:
- बच्चों के कमरे से घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखा खुला हुआ नहीं होना चाहिए।
- बच्चों की श्रेष्ठ उन्नति के लिए उनके कमरे का वास्तु के अनुकूल होना आवश्यक है।
- यदि उपर्युक्त तथ्यों में आपके बच्चों के कमरे में कोई कमी है, तो उसे परिवर्तित कर वास्तु के अनुकूल बना सकते हैं। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपके बच्चे के मानसिक विकास एवं उसकी ग्राह्य क्षमता में परिवर्तन नजर आएगा।

बजट तय करेगा बाजार की चाल

शेयर समीक्षा: बजट के बाद बाजार में तेजी की संभावना अधिक

मुंबई । शेयर बाजार की चाल अगले सप्ताह नये वित्त वर्ष के लिए एक फरवरी को जारी होने वाले बजट और विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख से तय होगी। विश्लेषकों के अनुसार, अगले सप्ताह संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश होगा। इस लिहाज से अगला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण और बेहद अस्थिर रहने वाला है लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि बाजार बहुत हल्के नोट पर बजट की ओर बढ़ रहा है। बजट के बाद बाजार में तेजी आने की संभावना अधिक है। पिछले साल भी इसी तरह का रुझान देखा गया था, जहां बाजार में बजट से पहले बिकवाली हुई लेकिन बजट के बाद तेजी आई थी। अगले सप्ताह बजट के अलावा, वैश्विक संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जहां वैश्विक बाजार ब्याज दर में बढ़ोतरी होने के संकेत के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है लेकिन भू-राजनीतिक अनिश्चितता प्रमुख चिंता का विषय है। डॉलर में तेजी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कंपनियों के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के परिणाम के लिहाज से अब तक का सत्र अच्छा रहा है। हालांकि अगले सप्ताह भी कई कंपनियों के परिणाम जारी होने हैं। इनके अलावा अगले सप्ताह एफआईआई के रुख का भी असर रहेगा। यह सप्ताह वाहन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक फरवरी को वाहन कंपनियां अपने मासिक बिक्री के आंकड़े पेश करेंगी।

एफआईआई ने 22000 करोड़ रुपए की बिकवाल की

बीते सप्ताह एफआईआई 22000 करोड़ रुपए के बिकवाल रहे हैं। हालांकि घरेलू निवेशकों डीआईआई ने एफआईआई की बिक्री के 50 प्रतिशत की भरपाई करने की कोशिश की है। उन्होंने नकद बाजार में लगभग 11000 करोड़ रुपए की लिवाली की है।

रिलायंस को सबसे ज्यादा नुकसान

टॉप 10 में से केवल एक कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। शेयर बाजारों में जबर्दस्त बिकवाली के बीच शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में 309178.44 करोड़ रुपए की गिरावट आई। बीते सप्ताह सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का बाजार पूंजीकरण बढ़ा। सप्ताह के दौरान एसबीआई की बाजार हैसियत 18340.07 करोड़ रुपए के उछाल के साथ 467069.54 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 96512.22 करोड़ रुपए घटकर 1579779.47 करोड़ रुपए पर आ गया। सबसे अधिक नुकसान में रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रही। टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 53488.29 करोड़ रुपए के नुकसान से 1365042.43 करोड़ रुपए रह गया। इन्फोसिस की बाजार हैसियत 42392.63 करोड़ रुपए घटकर 708751.77 करोड़ रुपए पर और एचडीएफसी बैंक की 31815.01 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ 811061.12 करोड़ रुपए पर आ गई। बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन 30333.64 करोड़ रुपए घटकर 414699.49 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई बैंक का 16291.53 करोड़ रुपए टूटकर 542407.86 करोड़ रुपए रह गया। भारती एयरटेल के बाजार मूल्यांकन में 15814.77 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 393174.23 करोड़ रुपए रह गया। एचडीएफसी की बाजार हैसियत 13319.96 करोड़ रुपए घटकर 456102.42 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान यूनिलीवर की 9210.39 करोड़ रुपए के नुकसान से 536411.69 करोड़ रुपए रह गई। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही।

अंतरराष्ट्रीय कॉल दो साल तक सुरक्षित रखनी होगी

दूरसंचार कंपनियों को सरकार का फरमान

नई दिल्ली । सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के जरिये विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को कम से कम दो साल के लिए सुरक्षित स्टोर रखने को अनिवार्य कर दिया है।

दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी एक परिपत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय कॉल एवं संदेशों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किया गया है। दूरसंचार विभाग ने यह कदम गत दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है जिसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट ब्योरे को दो साल के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया था। पहले यह प्रावधान सिर्फ एक साल के लिए ही लागू था। एकीकृत लाइसेंस धारक कंपनियों में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन जियो, बीएसएनएल हैं। वे अपने ग्राहकों को सैटेलाइट फोन सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं। विभाग की तरफ से जारी इस परिपत्र के मुताबिक, लाइसेंसधारक कंपनियों को कॉल डेटा रिकॉर्ड, आईपी रिकॉर्ड और सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड कम से कम दो साल के लिए स्टोर करने होंगे ताकि सरकार सुरक्षा कारणों से उनकी जांच कर सकें। दो साल की अवधि पूरा होने के बाद कंपनियां इस आंकड़े को नष्ट कर सकती हैं, बशर्ते कि किसी खास मामले में कोई निर्देश न दिया गया हो। एकीकृत लाइसेंस संबंधी प्रावधानों में किए गए बदलाव टाटा कम्युनिकेशंस, सिस्को वेबेक्स, एटीएंडटी ग्लोबल नेटवर्क पर भी लागू होंगे जिन्होंने इन लाइसेंसों को खरीदा है।

तीसरी तिमाही में विनिर्माण परिदृश्य सुधरा

पर कारोबार की लागत चिंता का विषय: फिक्की

नई दिल्ली। देश के विनिर्माण क्षेत्र के परिदृश्य में अक्टूबर-दिसंबर 2021 की तिमाही के दौरान सुधार हुआ है। हालांकि कारोबार की लागत चिंता का विषय है और नियुक्ति संभावनाएं कमजोर बनी हुई हैं। उद्योग मंडल फिक्की के एक सर्वे में यह निष्कर्ष निकाला गया है। फिक्की के विनिर्माण क्षेत्र पर तिमाही सर्वे के नतीजे रविवार को जारी किए गए। सर्वे के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां सतत रूप से जारी हैं। इस दौरान क्षमता इस्तेमाल 65 से 70 प्रतिशत के बीच रहा है। सर्वे में कहा गया है कि क्षेत्र में वृद्धि और निवेश के लिए विनिर्माताओं को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। आम बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है। फिक्की ने कहा कि सर्वे में शामिल 63 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि तीसरी तिमाही में उनका उत्पादन बढ़ा है। सर्वे में शामिल 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर 2021 की तिमाही में उनके पास इससे पिछली तिमाही जुलाई-सितंबर की तुलना में ऑर्डर बढ़े हैं। सर्वे में तीसरी तिमाही के दौरान 12 प्रमुख क्षेत्रों के विनिर्माताओं के प्रदर्शन और धारणा का आकलन किया गया है। इनमें वाहन, पूंजीगत सामान, सीमेंट, रसायन, उर्वरक और फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, चिकित्सा उपकरण, धातु और धातु उत्पाद, कागज के उत्पाद और टेक्सटाइल मशीनरी आदि क्षेत्र शामिल हैं।

इन कारणों के चलते विस्तार योजना प्रभावित

सर्वे में कहा गया कि कच्चे माल के ऊंचे दाम, वित्त की ऊंची लागत, मांग को लेकर अनिश्चितता, कार्यशील पूंजी की कमी, लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत, आपूर्ति श्रृंखला की दिक्कतों की वजह से कमजोर घरेलू और वैश्विक मांग कंपनियों की विस्तार योजना को प्रभावित कर रही है। सर्वे में बड़ी और लघु, मझोले उपक्रम क्षेत्र की 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयों की राय को शामिल किया गया है। इन इकाइयों का सम्मिलित सालाना कारोबार 2.7 लाख करोड़ रुपए है। सर्वे में शामिल आधे लोगों ने कहा कि तीसरी तिमाही में उनका निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, विनिर्माण क्षेत्र में नियुक्ति परिदृश्य कमजोर बना हुआ है।

कोयला आयात 22.5 प्रतिशत घटा

नवंबर में एक करोड़ 57 लाख 80 हजार टन रहा

नई दिल्ली । देश का कोयला आयात नवंबर, 2021 में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 22.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ एक करोड़ 57 लाख 80 हजार टन रहा है। कोयला एवं इस्पात के बारे में शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली कंपनी एमजंक्शन सर्विसेज ने आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रमुख एवं अन्य बंदरगाहों पर कोयला और कोक का आयात नवंबर में 22.5 प्रतिशत नीचे आया है। एमजंक्शन टाटा स्टील और सेल का संयुक्त उद्यम है। यह एक बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी है जो कोयला और इस्पात क्षेत्र पर शोध रपट भी प्रकाशित करती है। माह दर माह आधार पर तुलना की जाए तो नवंबर, 2021 में देश का कोयले का आयात मामूली 0.21 प्रतिशत बढ़ा है। अक्टूबर, 2021 में कोयला आयात एक करोड़ 57 लाख 50 हजार टन रहा था। नवंबर में कुल आयात में नॉन कोकिंग कोयले का हिस्सा 89.3 लाख टन रहा। यह नवंबर, 2020 में 1.37 करोड़ टन था। कोकिंग कोयले का आयात बढ़कर 49 लाख टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान महीने में 42.8 लाख टन था। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों अप्रैल-नवंबर में कुल कोयला आयात 13.88 करोड़ टन रहा है जो एक साल पहले की समान अवधि के 13.71 करोड़ टन के मुकाबले 1.25 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-नवंबर के दौरान नॉन कोकिंग कोयले का आयात 8.84 करोड़ टन रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 9.14 करोड़ टन से कम है। वहीं कोकिंग कोयले का आयात बढ़कर 3.54 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 2.81 करोड़ टन था। भारत की आयात मांग कम हुई है। ऐसे में समुद्री मार्ग से आयात के दाम घटने का मात्रा पर विशेष असर नहीं पड़ा है। यह रुख आगामी महीने में भी जारी रहने की उम्मीद है।

पीडीआईएल के लिए रुचि पत्र जमा करने की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार ने प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया, पीडीआईएल के संभावित खरीदारों के लिए रुचि पत्र जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपक ने 14 दिसंबर को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में सरकार की शतप्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए शुरुआती बोलियां आमंत्रित की थीं। इससे पहले ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। कोविड19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति और बोली लगाने वाली कंपनियों के आग्रह के बाद अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। दीपम की वेबसाइट पर एक नोटिस में यह जानकारी दी गई है। पीडीआईएल का गठन सात मार्च, 1978 को हुआ था। यह डिजाइन इंजीनियरिंग और संबद्ध परियोजना क्रियान्वयन सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग और सलाहकार सेवा प्रदान करती है। सरकार ने पीडीआईएल के लिए रिसर्जेंट इंडिया को लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही वह इस रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया का प्रबंधन भी करेगी। पीडीआईएल की रणनीतिक बिक्री अब अगले वित्त वर्ष में पूरी होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री से 12030 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें एयर इंडिया के निजीकरण से 2700 करोड़ रुपए और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से जुटाए गए 9330 करोड़ रुपए शामिल हैं।

हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने कदम उठा सकती है सरकार

नई दिल्ली। सरकार आगामी आम बजट में देश में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा कोष का आवंटन कर सकती है। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाना है। सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इस महीने की शुरुआत में बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने संकेत दिया था कि फरवरी में हरित हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी, जिसमें देश में हरित हाइड्रोजन को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय शामिल होंगे। 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। संभावना है कि बजट में हरित हाइड्रोजन खंड में अनुसंधान एवं विकास के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर पर सीमा शुल्क को घटाया जा सकता है। सीओपी26 में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का लक्ष्य प्राप्त करने और 2030 तक कुल बिजली जरूरत का 50 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है कि सरकार ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद सीईईडब्ल्यू का विचार है कि हरित हाइड्रोजन के कई औद्योगिक उपयोग हैं और यह लौह और इस्पात उद्योग को संभावित रूप से कॉर्बन मुक्त करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात 35 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। देश से समुद्री उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह अप्रैल-दिसंबर 2021 में 35 प्रतिशत बढ़कर 6.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 4.5 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दिसंबर, 2021 में समुद्री उत्पादों का निर्यात 28 प्रतिशत बढ़कर 72.05 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। देश के पांच प्रमुख निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, चीन, जापान, वियतनाम और थाइलैंड शामिल हैं। देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात में मूल्य के हिसाब से सबसे अधिक 74 प्रतिशत हिस्सा झींगे का रहा। इसके अलावा फ्रोजन मछली का हिस्सा सात प्रतिशत तथा स्क्विड का हिस्सा पांच प्रतिशत रहा। मई, 2020 में पेश की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली निर्यात का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन और आने वाले वर्षों में 55 लाख रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों को मिले पीएलआई योजना का लाभ

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट के ठीक पहले उद्योग मंडल सीआईआई ने रविवार को कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं में सृजित रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन की अतिरिक्त दरें भी जोड़ी जानी चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने सुझाव दिया है कि अधिक संख्या में रोजगार देने वाले चमड़ा एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को निवेश आकर्षित करने और नए रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहन योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, महामारी की मार से उबर रहे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमारा यह सुझाव है कि बजट में प्रोत्साहन योजनाओं के भीतर रोजगार सृजन का पहलू भी जोड़ा जाए। उद्योग मंडल ने कहा कि अधिक संख्या में रोजगार देने वाले क्षेत्रों को पीएलआई योजनाओं के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा। अधिक संख्या में रोजगार देने वाले क्षेत्रों को अधिक रियायतें दी जानी चाहिए।

तीसरी लहर का घरों की बिक्री पर मामूली असर

घरों की मांग मजबूत रहने की उम्मीद : उद्योग

नई दिल्ली । कोविड19 महामारी की तीसरी लहर से घरों की बिक्री पर विशेष असर पड़ने की संभावना नहीं है। जनवरी-मार्च की मौजूदा तिमाही में भी घरों की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। कई राज्यों ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू जैसे अंकुश लगाए हैं, जिससे परियोजना स्थलों पर संभावित ग्राहकों की आवाजाही पर असर पड़ा है। हालांकि रियल एस्टेट डेवलपर और संपत्ति सलाहकारों का मानना है कि जनवरी के पहले दो सप्ताह में इसका मामूली असर ही पड़ा है और बिक्री के लिए पूछताछ मजबूत बनी हुई है। एनेरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, घरों की बिक्री पर ओमिक्रॉन का प्रभाव पिछली दो लहरों की तुलना में सीमित रहने की संभावना है। एनेरॉक देश की प्रमुख आवासीय ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है। उन्होंने कहा, पिछली दो लहरों की तुलना में इस बार पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है और आवाजाही प्रभावित नहीं हुई है। धारणा व्यापक रूप से सकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि इस लहर में मृत्यु दर काफी कम है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी काफी कम है। हालांकि कुछ शहरों में सप्ताहांत के लॉकडाउन ने परियोजना स्थल पर संभावित ग्राहकों की आवाजाही को प्रभावित किया है। लेकिन डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिये रियल एस्टेट कंपनियों ने अपनी बिक्री की रफ्तार को कायम रखा है। 2021 में भारत में आवासीय अचल संपत्ति बाजार ने उल्लेखनीय रूप से पुनरुद्धार दर्ज किया है।

परिधान निर्यातकों की नए बाजारों पर नजर

नई दिल्ली। परिधान निर्यातकों की निगाह लातिनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे नए बाजारों पर है। परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद एईपीसी को चालू वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष में देश से होने वाले निर्यात में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, दूसरी ओर कच्चे माल की कीमतें उद्योग के लिए चिंता का विषय हैं। एईपीसी के चेयरमैन नरेंद्र गोयनका ने कहा कि क्षेत्र के लिए निर्यात अवसरों का पता लगाने के लिए परिषद विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, हम नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं। हमारे लिए वहां निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं। चालू वित्त वर्ष में 16.5 अरब डॉलर तक का और 2022-23 में 19 अरब डॉलर तक का निर्यात होने की उम्मीद है। परिधान के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि होने वाली है। उन्होंने कहा कि मानवनिर्मित रेशे और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना से निवेश लाने में मदद मिलेगी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश से होने वाला निर्यात भी बढ़ेगा। गोयनका ने कहा कि अभी क्षेत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हैं।

पी-नोट्स के जरिये निवेश बढ़ा

दिसंबर तक बढ़कर 95501 करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली । भारतीय पूंजी बाजारों में पार्टिसिपेटरी नोट्स पी-नोट्स के जरिये निवेश दिसंबर 2021 के अंत तक बढ़कर 95501 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले महीने पी-नोट्स के जरिये निवेश का प्रवाह स्थिर या नकारात्मक रहेगा।

पी-नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं, जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में कारोबार करना चाहते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें उचित जांच परख की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बाजारों में पी-नोट्स के जरिये निवेश का मूल्य दिसंबर, 2021 के अंत तक बढ़कर 95501 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो नवंबर के अंत तक 94826 रुपए था। इनमें शेयर, बांड और हाइब्रिड प्रतिभूतियां तीनों शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर के अंत में निवेश का स्तर 1.02 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्चए 2018 के बाद सबसे अधिक था। उस समय पी-नोट्स के जरिये निवेश 1.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। दिसंबर के पी-नोट्स के आंकड़े एक सपाट प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इनसे पता चलता है कि शेयरों में लगभग 675 करोड़ रुपए और ऋण या बांड बाजार में 716 करोड़ रुपए का प्रवाह हुआ है। पी-नोट्स के जरिये निवेश का यह प्रवाह हैरान करने वाला है क्योंकि एफपीआई ने दिसंबर में शेयर और बांड बाजार में जबर्दस्त बिकवाली की है। इस दौरान उन्होंने शेयर बाजारों से 19026 करोड़ रुपए और बांड बाजार से 11799 करोड़ रुपए निकाले हैं। दिसंबर 2021 तक पी-नोट्स के जरिये कुल 95501 करोड़ रुपए के निवेश में से 84948 करोड़ रुपए शेयरों में, 10322 करोड़ रुपए बांड में, 231 करोड़ रुपए हाइब्रिड प्रतिभूतियों में डाले गए हैं।

बीते साल इस्पात उत्पादन बढ़ा

नई दिल्ली। भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2021 में 18 फीसदी बढ़कर 11.8 करोड़ टन हो गया, वहीं इस मामले में विश्व में अगुआ चीन में इस्पात उत्पादन तीन फीसदी घटकर 103.28 करोड़ टन हो गया। वैश्विक उद्योग संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दूसरे बड़े इस्पात उत्पादक देश भारत ने 2020 में 10.03 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया था वहीं चीन ने इसी अवधि में 106.47 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया। वर्ल्डस्टील ने कहा, 2021 में विश्व में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 195.05 करोड़ टन था जो 2020 के कुल उत्पादन 188.04 करोड़ टन से 3.7 फीसदी अधिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जापान ने 9.63 करोड़ टन इस्पात उत्पादन किया, 2020 में उसने 8.32 करोड़ टन इस्पात उत्पादन किया। अमेरिका का उत्पादन इस वर्ष 8.6 करोड़ टन रहा जो इससे एक वर्ष पहले 7.27 करोड़ टन था। रूस का उत्पादन 7.6 करोड़ टन, दक्षिण कोरिया का 7.06 करोड़ टन, तुर्की का 4.04 करोड़ टन, जर्मनी का 4.01 करोड़ टन रहा।

बजट में 80सी के तहत सीमा बढ़ने की संभावना

इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्कों को युक्तिसंगत किए जाने की उम्मीद

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को जब अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी तो सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि सरकार राजकोषीय मजबूती की कसौटी और लोक लुभावन उपायों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर पाती है। देश के कॉरपोरेट जगत को आम बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जिनके बल पर वे अपने वृद्धि के एजेंडा को फिर से तय कर सकें। वहीं आम करदाता अपने हाथ में खर्च योग्य आय बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, ताकि वह निवेश कर सके और उपभोग बढ़ा सके। बजट को लेकर बाजार को प्रत्यक्ष कर मामले में उम्मीद है कि 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की करमुक्तता को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जाए। साथ ही वैकल्पिक रियायती कर व्यवस्था को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए इसके तहत सर्वाधिक 30 प्रतिशत कर दर के लिए 15 लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाया जाए। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लगने वाला कर एलटीसीजी निवेशकों के भरोसे को आघात पहुंचाता है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यह कर नहीं होता। भारत में भी उम्मीद की जा रही है

कि सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री पर इस कर में छूट दी जाए जिससे शेयर बाजार के जरिये निवेश बढ़ेगा। कॉरपोरेट जगत को कोविड19 के दौरान समाज और कर्मचारी कल्याण पर आए खर्च या इसके बड़े हिस्से पर कर में छूट की उम्मीद है। बजट में अप्रत्यक्ष कर को लेकर विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सहायक पुर्जों, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन उपकरणों और इससे संबंधित घटकों के लिए सीमा शुल्क कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाए। सेमीकंडक्टर विनिर्माताओं के लिए क्षेत्र विशेष छूट दी जा सकती है। उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना के विस्तार के लिए बजट आवंटन दिया जा सकता है। जांच के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट का विस्तार हो सकता है

क्या है विशेषज्ञों की राय

नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि कोविड संकट से पड़े असर के बावजूद बड़े कारोबार और उच्च मध्यम वर्ग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य रूप से ध्यान रोजगार, आय और मांग निर्माण के इर्दगिर्द परिवेश बनाने पर होना चाहिए। डेलॉइट इंडिया के भागीदार गोकुल चौधरी ने कहा कि बजट से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जहां महंगाई के कारण खर्च करने योग्य आय पर असर पड़ा है। एएमआरजी के भागीदार रजत मोहन ने कहा कि मध्यम वर्ग जहां तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए खर्च करने योग्य आय बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, वहीं बड़ी कंपनियों को कर ढांचे में स्थिरता की तथा एमएसएमई को कारोबार में विकास के लिए अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होने की अपेक्षा है।

प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा चाहता है स्वास्थ्य सेवा उद्योग

तीन प्रतिशत जीडीपी आवंटन की मांग

नई दिल्ली । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बजट में खुद के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा चाहता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को उम्मीद है कि इस बार बजट में क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का तीन प्रतिशत किया जाएगा। निजी क्षेत्र की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनियों ने कहा है कि सरकार को बजट में कर प्रोत्साहन को जारी रखनेए छोटे शहरों में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन और श्रमबल का कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक आशुतोष रघुवंशी ने कहा, सरकार ने 2021 के बजट में स्वास्थ्य और जीवन को पहले छह स्तंभों में रखा था। 2022 में भी इसे जारी रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा ढांचे के लिए आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं में जांच केंद्रों, वेंटिलेंटर, आईसीयू, क्रिटिकल केयर सुविधाएं और ऑक्सीजन संयंत्र लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोग निरोधक स्वास्थ्य, जांच और परीक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने को तत्काल एक अलग बजट आवंटन की जरूरत है। रघुवंशी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स की कार्यकारी वाइस चेयरमैन प्रीता रेड्डी ने कहा कि तात्कालिक आधार पर स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का तीन प्रतिशत किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे ढांचे और संसाधनों में अंतर को पाटा जा सके।

भारत बनाम वेस्टइंडीज एकदिवसीय और टी20 सीरीज

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एकदिवसीय में उतरते ही रिकार्ड बनाएगी भारतीय टीम

मुबई (एजेंसी)।

भारतीय टीम 6 फरवरी से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू एकदिवसीय और टी20 सीरीज खेलने जा रही है। रोहित शर्मा की कसानी में तीन-तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम इस सीरीज के पहले ही एकदिवसीय मैच में उतरते ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम करेगी। इस मैच में उतरते ही भारतीय टीम अपना 1000वां एकदिवसीय मैच खेलेगी।इस प्रकार भारतीय टीम 1000 वां एकदिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। भारतीय टीम ने अपना पहला एकदिवसीय मैच साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तब एकदिवसीय मैच 60 ओवर्स का खेला जाता था। अब तक सबसे ज्यादा एकदिवसीय मैच खेलने वाली तीन टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया ओर पाकिस्तान हैं। भारत ने अपने 999 मैचों में से 518, जीते हैं जबकि 431 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम हैं उसने 958 मैच खेले हैं। जिसमें 581 जीते हैं जबकि उसे 334 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं तीसरे टीम पाकिस्तान ने 936 मैच खेलकर 490 जीते हैं और उसे 417 में हार मिली है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे श्रृंखला के लिए अहमदाबाद पहुंची भारतीय टीम

अहमदाबाद। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य छह फरवरी से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए यहां पहुंच गए हैं। सभी खिलाड़ियों ने रविवार और सोमवार के बीच जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में प्रवेश किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ''वे तीन दिन तक पृथकवास में रहेंगे।'' रोहित शर्मा इस श्रृंखला के दौरान पहली बार भारत की सीमित ओवरों की टीम के नियमित कप्तान के रूप में उतरेंगे। वह पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका नहीं जा पाए थे। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शनिवार को अहमदाबाद के लिए अपनी रवानगी की तस्वीर पोस्ट की थी। वह विमान में शिखर धवन के साथ बैठे थे। स्पिनर कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है जबकि लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार टीम में जगह मिली है। कोविड-19 के जोखिम को देखते हुए बीसीसीआई ने तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन स्थल की संख्या घटाकर दो कर दी है। तीनों टी20 कोलकाता में खेले जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखला जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत पहुंचेगी।

फीडे महिला कैंडीडेट शतरंज - कोनेरु हम्पी होंगी एकमात्र भारतीय

नई दिल्ली (एजेंसी)।

विश्व महिला शतरंज चैम्पियन चीन की जू वेंजून के ताज को कौन चुनौती देगा यह इस वर्ष के पहले भाग मे तय हो जाएगा । विश्व शतरंज संघ जल्द ही समय और स्थान की घोषणा कर सकता है पर इससे पहले इसमें खेलने वाली सभी महिला खिलाड़ियों के चयन की घोषणा कर दी गयी है । पिछले 2 बर्ष से चल रही विभिन्न प्रतियोगितों के बाद सभी आठ खिलाड़ी क्रमशः इस प्रकार है - अलेक्सान्द्रा गोरयाचकिना (रूस), कोनेरु हम्पी (भारत) ,लागनों काटेरयना (रूस) , ली टिंगजे (चीन) , अलेक्ज़ेंड्रा कोस्टेनियुक (रूस) ,तान ज़्होंगयी (चीन) अन्ना मुजयचूक और मारिया मुजयचूक (दोनों उक्रेन) । प्रतियोगिता मे रूस की 3 , चीन और उक्रेन की 2 जबकि भारत की एकमात्र खिलाड़ी कोनेरु हम्पी जगह बनाने मे कामयाब रही है । पूर्व विश्व रैपिड चैम्पियन हम्पी के लिए क्लासिकल विश्व चैम्पियन बनने के उनके सपने को पूरा करने का यह सुनहरा मौका होगा और देखना होगा की क्या वह फीडे कैंडीडेट जीतकर विश्व चैम्पियन चीन की जू वेंजून को चुनौती पेश करेंगी ।प्रतियोगिता मे डबल राउंड रॉबिन के आधार पर 14 क्लासिकल मुक़ाबले खेले जाएंगे ।

ब्रेसनन ने खेल को अलविदा कहा

लंदन (एजेंसी)।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर टिम ब्रेसनन ने खेल को अलविदा कह दिया है। ब्रेसनन काउंटी टीम वारविकशायर की ओर से खेलते हैं। उसने भी ब्रेसनन के खेल को अलविदा कहने की बात मानी है। ब्रेसनन ने कहा कि संन्यास का यह फैसला बेहद कठिन रहा पर तकालीन प्रशिक्षण में लौटने के बाद मुझे लगा कि यह सही समय है। मैंने काउंटी में अपने 21वें पेशेवर वर्ष की तैयारी के लिए पूरे ऑफ-सीजन में कड़ी मेहनत करना जारी रखा लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब अपने और अपने साथियों के लिए उच्च स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाता।

उन्होंने कहा कि मैं जिस खेल से प्यार करता हूं, उसके लिए मेरे पास जो उत्साह है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मैं 2022 सीजन से निपटने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरा शरीर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने करियर और वारविकशायर को बड़े गर्व के साथ देखूंगा और देश का प्रतिनिधित्व करना एक पूर्ण सम्मान की बात है। बड़े होकर मैंने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि मैं कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के साथ और कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों के खिलाफ खेलने के लिए कितना भाग्यशाली था।

वारविकशायर क्रिकेट के अनुसार अपने प्रथम श्रेणी करियर में ब्रेसनन ने 7,138 रन बनाए जिसमें 7 शतक और 9 बार पांच विकेट लेने के साथ कुल 575 विकेट शामिल हैं। ब्रेसनन इंग्लैंड की उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने पहली बार 2010 विश्व टी20 ट्रॉफी हासिल की थी।

शाहरुख और साई वेस्टइंडीज सीरीज में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे: बीसीसीआई

मुबई (एजेंसी)।

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के बल्लेबाज एम शाहरुख खान और स्पिनर रवि श्रीनिवास साई किशोर को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली छह मैचों की सीमित ओवरों की सीरीज के लिए रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम में जगह दी गयी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी के अनुसार हाल में शाहरुख ओर रवि का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन दोनो को इसलिए शामिल किया गया है ताकि अगर संक्रमण से किसी खिलाड़ी को बाहर होना पड़ा तो विकल्प के तौर पर इन्हें शामिल किया जा सकता है। बीसीसीआई अधिकारी के अनुसार ये दोनो ही खिलाड़ी मुख्य टीम के खिलाड़ियों के साथ बायो-बबल (जैव सुरक्षित माहौल) में भी रहेंगे। भारत ओर वेस्टइंडीज के बीच 6 फरवरी से सीमित ओवरों की तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज शुरु होगी। यह सीरीज अहमदाबाद में खेली जाएगी। इसके बाद तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज कोलकाता में होगी। स्पिनर साई गत वर्ष श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम में नेट गेंदबाजों के समूह में शामिल थे। वह दूसरी बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किये गये हैं। वहीं बल्लेबाज शाहरुख पिछले कुछ समय से अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण टीम में जगह के दावेदार बने हुए हैं। इस सत्र में कर्नाटक के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

इंडियन सुपर लीग: डूबती नैया को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे गोवा और ओड़िसा

बैम्बोलिन । एफसी गोवा जानती है कि उसके हाथ से समय निकला जा रहे हैं और हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2021-22 में उसकी डूबती नैया को आगामी मैच में जीत कुछ हद तक थामेगी। लेकिन मंगलवार को बैम्बोलिन स्थित जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम में उसका सामना ओड़िसा एफसी के रूप ऐसे प्रतिद्वंदवी होगा, जो अपने अभियान को जीत की पटरी पर वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। गोवा पिछले चार मैचों से जीत से दूर है और 14 मैचों में 14 अंक लेकर तालिका में नौवें स्थान पर है। कोच डेरिक परेरा की टीम अपने पिछले मैच में आकर्षक फुटबाल खेलने के बावजूद जमशेदपुर से हार गई थी। परेरा जानते हैं कि जीत की राह पर चलने के लिए उनके लड़कों मिलने वाले अवसरों को भुनाना होगा। अगर गोवा को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे अभी से मैच जीतने शुरू करने पड़ेंगे लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ओड़िसा की स्थिति भी समान है।

ओड़िसा 13 मैचों में पांच जीत और दो ड्रा से 17 अंक लेकर तालिका में आठवें स्थान पर है। गोवा के लिए गोल नहीं करना एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि उसने सीजन में अन्य टीमों की तुलना में स्कोरिंग के अवसर बहुत बनाए और ज्यादा शॉट लगाने के प्रयास किए हैं। जमशेदपुर के खिलाफ पिछले मैच में गोवा के तीन शॉट गोलपोस्ट या क्रॉसबार में लगे, जो कि इस सीजन के मैच में सबसे ज्यादा है। कोच परेरा ने कहा, 'हमारा इरादा हमेशा तीन अंक हासिल करना होता है और हम लड़ते रहेंगे। हम कभी हार नहीं मानेंगे।' उधर, ओड़िसा पिछला मैच हारने के बावजूद गोल कर रही है और देर से गोल करने की क्षमता से कोच किनो गार्सिया को खुश होना चाहिए। क्रिस्टियन जोनाथस भी पिछले मैच में गोल करने वालों में शामिल थे और वो इस सीजन में मैच के अंतिम 15 मिनट में ओड़िसा का नौवां गोल था। जोनाथस चार गोल कर चुके हैं और केवल अरिदाई कैबरेरा (5) ने ओड़िसा के लिए उनसे अधिक गोल किए हैं। गार्सिया ने कहा, 'पिछले मैचों में हम अच्छा खेल रहे हैं। हम जीते नहीं या फिर अंक प्राप्त नहीं कर पाए लेकिन हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा था। सकारात्मक बात यह है कि टीम ने उन चीजों को आजमाने में बहादुरी दिखाई है जिनकी ट्रेनिंग हमने की है। हम गेंद अपने नियंत्रण में रख करके ज्यादा मौके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों का रवैया अच्छा है। यह एक कड़ा मुकाबला होगा। गोवा उस स्थान के लायक नहीं है, जहां वो है। वो काफी अच्छा खेल रही है। पिछली बार सीजन के पहले चरण में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थीं, तो वो मुकाबला 1-1 से बराबरी पर छूटा था।

होल्डर की हैट्रिक से वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया , 3-2 से सीरीज जीती

ब्रिजटाउन ।(एजेंसी)।

ऑलराउंडर जैसन होल्डर की घातक गेंदबाजी से मेजबान वेस्टइंडिज ने पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 17 रन से हराकर श्रृंखला 3-2 से जीत ली है। होल्डर ने अंतिम चार गेंदों में चार विकेट लेकर एक अहम रिकार्ड भी अपने नाम किया है। वह वेस्टइंडीज की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।

वेस्टइंडीज ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 179 रन बनाए। कीरोन पोलार्ड ने सबसे ज्यादा 41 और रोवमैन पावेल ने 35 रनों का योगदान दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम इंग्लैंड केवल 162 रन ही बना पायी। इंग्लैंड की तरफ से जेम्स विन्से ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए , वहीं बाकि बल्लेबाज नाकाम रहे। इंग्लैंड ने 19 ओवर में छह विकेट पर 160 रन बना लिए थे और उसके पास जीत दर्ज करने का अवसर था पर होल्डर ने अंतिम ओवर में

जोर्डन को 7 जबकि सैम बिलिंग्स को 41 रन पर आउट करने के बाद आदिल राशिद और साकिब महमूद को भी आउट कर अपनी टीम को जीत दिला दी। इसके साथ ही वह चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाले एक विशेष क्लब में भी शामिल हो गए हैं। होल्डर से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में लसिथ मलिंगा, राशिद खान और कर्टिस कैंपर ने रिकार्ड बनाया था। इस क्रिकेटर ने 2.5 ओवर में 27 रन देकर कुल पांच विकेट लिए। होल्डर के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 30 रन पर चार विकेट लिए।

आईपीएल में अय्यर , कमिंस सहित इन खिलाड़ियों पर लग सकती है करोड़ों की बोली

मुम्बई। आईपीएल के 15 वें सत्र के होने वाली मेगा नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। इसमें इस बार आठ की जगह दस टीमें भाग लेंगी। इस नीलामी की नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद हैं। नीलामी में श्रेयस अय्यर , पैट कमिंस सहित पांच खिलाड़ियों पर करोड़ों की रकम लगायी जा सकती है।

श्रेयस अय्यर = श्रेयस अय्यर टी20 लीग के पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से उतरे थे पर इस बार उन्होंने दिल्ली छोड़ दी है और ऐसे में आरसीबी और केकेआर जैसी टीमें उन्हें बड़ी रकम देकर खरीद सकती हैं। श्रेयस का आधर मूल्य 2 करोड़ रुपए रखा गया है।

पैट कमिंस = ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस पिछले सीजन में केकेआर की ओर से उतरे थे। उन्होंने एशेज में भी अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में वे टी20 में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में सभी टीमों उन्हें खरीदना चाहेंगी।

डेविड वॉर्नर = अनुभवी बल्लेबाज डेविड वार्नर पिछले बार सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे पर सत्र के बीच में ही टीम ने उन्हें हटा दिया था। वह आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज हैं, ऐसे में कई टीमें उन्हें बड़ी रकम देकर खरीद सकती हैं।.

कागिसो रबाडाः दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शानदार प्रदर्शन किया था। वह अभी विश्व के सबसे बेहतर गेंदबाजों में शामिल हैं। ऐसे में उनपर टीमें बड़ी बोली लगा सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से श्रीलंका को लगा झटका, ये क्रिकेटर पाया गया कोरोना पॉजिटिव

कोलंबो। श्रीलंका के अनकैप्ड गेंदबाज नुवान तुषारा कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। तुषारा के अलावा दौरे के लिए श्रीलंका की 20 सदस्यीय टीम में शामिल हैं जिसमें पांच टी20 इंटरनेशनल शामिल हैं। टीम के ट्रेनर दिलशान फोन्सेका भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तीन फरवरी को टीम के ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले ये मामले सामने आए हैं। दोनों दस्ते और सहयोगी स्टाफ के बीच किए गए एक नियमित पीसीआर परीक्षण के दौरान पॉजिटिव मामले पाए गए जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम के प्रस्थान से पहले बायो-सिक्योर बबल में हैं। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने सोमवार को एक बयान में कहा, दोनों वर्तमान में कोविड-19 प्रोटोकॉल से गुजर रहे हैं और 10 फरवरी को टीम में फिर से शामिल हो जाएंगे।

लद्दाख में बनेगा अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम = मोदी

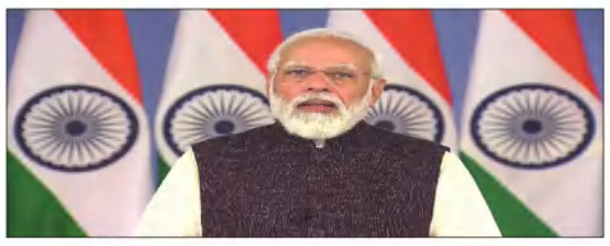

नई दिल्ली। लद्दाख के लोगों को अब शीघ्र ही एक फुटबॉल स्टेडियम मिलने जा रहा है। 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर बनने वाले इस अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में एक सिंथेटिक ट्रैक भी रहेगा। इसके साथ ही 1000 की क्षमता वाला एक हॉस्टल भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टेडियम को बनाये जाने की घोषणा करते हुए कहा है कि लद्दाख के लोगों को सरकार शीघ्र ही सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। यह स्टेडियम दस हज़ार फुट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होगा। लदाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30 हज़ार दर्शक एक साथ खेल देखने का आनंद ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आधुनिक स्टेडियम में आठ लेन का एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहां एक हज़ार बेड वाले, एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। इससे बड़ी बात यह है कि इस स्टेडियम को विश्व फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी प्रमाणित किया है। साथ ही कहा कि जब खेल का ऐसा कोई बड़ा ढांचा तैयार होता है तो इससे युवाओं को बेहतरीन अवसर भी मिलते हैं। स्टेडियम बनने के बाद यहां के युवाओं को और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी।

ऑस्ट्रेलियन ओपन : नडाल ने रचा इतिहास, जीता 21वां ग्रैंड स्लैम

मेलबर्न (एजेंसी)।

स्पेन के राफेल नडाल ने दो सेट हारने के बाद करिश्माई वापसी करते हुए रविवार को रूस के दानिल मेदवेदेव को पांच सेटों के मैराथन संघर्ष में 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 से हराकर रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लेम खिताब जीत लिया। नडाल ने मेदवेदेव के खिलाफ पांच घंटे 24 मिनट तक चले मुकाबले में जीत दर्ज की। नडाल इस जीत के साथ सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर से आगे निकल गए हैं जिनके नाम 20-20 ग्रैंड स्लेम खिताब हैं। नडाल का यह दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। उन्होंने 13 साल के अंतराल के बाद जाकर यह खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2009 में पहली बार यह खिताब जीता था जबकि वह 2012, 2014, 2017 और 2019 में मेलबर्न फाइनल में हारे थे। स्पेन के नडाल का ग्रैंड स्लेम फाइनल में अब 21-8 का रिकॉर्ड हो गया है। वर्ष 2019 में जोकोविच के हाथों मेलबर्न फाइनल हारने के बाद ग्रैंड स्लेम फाइनल में नडाल की यह लगातार चौथी जीत है। दूसरी तरफ मेदवेदेव की ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में यह लगातार दूसरी हार है। पिछले वर्ष फरवरी में जोकोविच ने उन्हें फाइनल में हराया था। ग्रैंड स्लेम फाइनल्स में उनका रिकॉर्ड अब 1-3 हो गया है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत मेरे करियर की सबसे बड़ी वापसी: नडाल

दुनिया के नंबर पांच टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रविवार को यहां दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव को हरा कर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीतने के बाद कहा कि यह मैच उनके करियर की सबसे बड़ी वापसी थी। नडाल ने कहा, 'अगर आप हर संभव प्रयास करें और अपना सब कुछ दांव पर लगा दें तो आपकी जीत की संभावना ज्यादा होती है। मैं कह सकता हूं कि यह मेरे टेनिस करियर की सबसे बड़ी वापसी है। बेशक अंत में जीत ही इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं, लेकिन जिस तरह से आप मैच जीतते हैं, खासतौर पर व्यक्तिगत भावनाओं के लिहाज से, वह अलग है। जिस तरह से मैंने आज रात इस ट्रॉफी को हासिल किया वह अविस्मरणीय था। निसंदेह यह मेरे टेनिस करियर के सबसे भावनात्मक मैचों में से एक था। यह जीत मेरे लिए बहुत मायने रखती है।% उल्लेखनीय है कि नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में जबरदस्त वापसी करते हुए खिताब जीता था। वह पहले दो सेटों में रूसी प्रतिद्वंद्वी मेदवेदेव से 2-6, 6-7(5) से पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने लगातार तीन सेट 6-4, 6-4, 7-5 से जीत कर 21वां ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने वाले दुनिया के इकलौते टेनिस खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2005 में 19 वर्ष की उम्र में फ्रेंच ओपन खिताब जीत कर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। नडाल ने 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने पर कहा, 'मेरे करियर के इस क्षण में एक और ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करना शानदार है। बेशक मुझे पता है कि 21 एक विशेष संख्या है। मुझे पता है कि इसके क्या मायने हैं, लेकिन मेरी लिए आज का दिन अविस्मरणीय है। मैं अपने टेनिस करियर में एक और खास चीज हासिल करके भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।' स्पैनिश खिलाड़ी ने प्रतिद्वंद्वी मेदवेदेव की प्रशंसा करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि डेनियल एक महान चैंपियन हैं। उन्होंने हार को परिपक्व तरीके से स्वीकार किया और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत कठिन दिन है। मुझे पता है कि उस स्थिति में होना कितना कठिन है।'

यूपी में 5 साल पहले दंगाई ही कानून थे : पीएम मोदी

राजेश अलख

नई दिल्ली, 31 जनवरी । पीएम मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पहली डिजिटल रैली में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार और गुंडे, माफिया और दंगाइयों पर निशाना साधा।

मोदी ने पहली डिजिटल रैली में कहा कि हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं जबकि वो आपसे बदला लेने की ठानकर बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि पांच साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा शासन का आदेश था लेकिन पांच साल में योगी सरकार उप्र को इन हालातों से बाहर निकालकर लाई है और ये कोई मामूली कार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों बागपत, शामली, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से जुड़े मतदाताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। मोदी ने कहा, ''मैं देखकर खुश हूं कि उप्र के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान, बहुत सतर्क हैं, उप्र की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है और इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाना है।''

पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ''कोई भूल नहीं सकता कि पांच साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। पांच साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे उन्हीं का कहा शासन का आदेश था, पांच साल पहले व्यापारी लुटता, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब यह क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी।''

उन्होंने कहा, ''पांच साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर-जमीन-दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आये दिन खबर आती थीं, अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को व्यापारियों को तबाह कर रख दिया, पांच साल में योगी सरकार उप्र को इन हालातों से बाहर निकालकर लाई है और ये कोई मामूली कार्य नहीं है।''

पश्चिमी उप्र के पांच जिलों की 21 विधानसभा क्षेत्रों के 98 मंडल इकाईयों (भाजपा की प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक इकाई) पर सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ''हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट हैंड वोटर (जो पहली बार मतदान करने जा रहे) वे उत्साह और उमंग से भरे हैं भाजपा की सरकार बनाने के लिए। वे खुलकर भाजपा के साथ हैं। युवा भी समझ रहे हैं कि अब फरि से यूपी को गुंडे माफियाओं के हवाले नहीं करना है।''

मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''पश्चिमी उप्र की ये वह धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने देश को बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा।''

प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बिना नाम लिए उन पर तंज कसते हुए कहा, ''जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों

पर भरोसा नहीं करते क्या वे यूपी के युवाओं की प्रतिभा का सम्मान कर सकते हैं। यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है।''

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अखिलेश यादव ने कोरोना टीका को भाजपा की वैक्सीन बताते हुए इससे सावधान रहने को कहा था।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण

राजेश अलख

वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8-8.5 फीसदी रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 31 जनवरी । आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आरंभ हो चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इकोनॉमिक सर्वे 2022 पेश किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और यह 2022-23 की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को लोकसभा में पेश आर्थिक समीक्षा 2021-22 में यह बात कही गई है।

समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। अगले वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8-8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि देश में आर्थिक मोर्चे पर सभी गतिविधियों के रफ्तार पकड़ने, कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में तेजी और आपूर्ति की प्रक्रिया में तेजी आने से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर स्थिति है। इसके चलते देश की जीडीपी आठ से साढे आठ प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

इसमें कहा गया है कि फिर भी वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक नई लहर दुनिया भर में फैल रही है और अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ने से प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा धन की निकासी शुरू कर दी गई है।

इसमें कहा गया है वैश्विक महामारी के कारण सभी तरह की दिक्कतों के बावजूद, भारत का भुगतान संतुलन पिछले दो वर्षों में अधिशेष में रहा। इस प्रवृत्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार जमा करने के लिए प्रेरित किया। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ते निर्यात से होने वाली आय वर्ष 2022-23 में विश्व में संभावित तरलता की कमी के खिलाफ पर्याप्त सहारा प्रदान करेगा।

संसद में सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया है कि सरकार के पास समर्थन बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर पूंजीगत खर्च बढ़ाने की वित्तीय क्षमता है। राजस्व में मजबूत पुनरुद्धार सरकार को आवश्यक होने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय स्थान भी प्रदान करता है।

अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा और सरकारी कर्ज बढ़ गया।

हालांकि, 2021-22 में अब तक सरकारी राजस्व में जोरदार उछाल देखने को मिला है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2 प्रतिशत (साल दर साल) की वृद्धि हुई है, जबकि 2021-22 के बजट अनुमानों में 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों के लिए कर संग्रह में उछाल आया है। जुलाई 2021 से सकल मासिक जीएसटी संग्रह लगातार 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।

निरंतर रेवेन्यू कलेक्शन और सरकार द्वारा लक्षित व्यय नीति के कारण, अप्रैल-नवंबर 2021 के लिए राजकोषीय घाटा बजट अनुमान (बीई) के 46.2 प्रतिशत पर समाहित किया गया है, जो कि इसी अवधि के दौरान प्राप्त अनुपात का लगभग एक तिहाई है। यह पिछले दो वर्षों में (अप्रैल-नवंबर2020 में बीई का 135.1 प्रतिशत और अप्रैल-नवंबर 2019 में बीई का 114.8 प्रतिशत) है। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान अपने स्तर से लगभग आधा हो गया। सर्वेक्षण में कहा गया है, 'इसका मतलब यह है कि सरकार के पास समर्थन बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने की वित्तीय क्षमता है। यदि आवश्यक हो तो राजस्व में मजबूत पुनरुद्धार सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय स्थान भी प्रदान करता है।'

दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में खाली पदों पर भर्ती तेजी से करे गृह मंत्रालय- संसदीय समिति

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय पुलिस बलों में खाली पदों पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। समिति ने मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक और सिपाही के रक्ति पदों को भरने के लिए शुरू की गयी प्रक्रिया के बावजूद सैकड़ों पद खाली रहेंगे।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रक्ति पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की तत्काल आवश्यकता है। उसका मानना है कि इन रक्तियों के कारण पुलिस बल के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कर्मचारी चचन आयोग के साथ बातचीत की जानी चाहिए। रिपोर्ट में केन्द्रीय पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट और इससे उपर के लगभग 700 पदों को भरने की प्रक्रिया पर संतोष जताया गया है लेकिन कहा है कि इसके बाद भी इन बलों में सैकड़ों पद रक्ति रहेंगे जिन्हें तत्काल आधार पर भरा जाना चाहिए क्योंकि इसका बलों की निर्णय लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है।

समिति ने केन्द्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की बढ़ती संख्या की सराहना करते हुए कहा है कि महिलाओं को इन बलों में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता और संवाद सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। समिति ने पुलिसकर्मियों के लिए आवास की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाने तथा आवासों के निर्माण के कार्य में तेजी लाने को कहा है।

संसद में पेगासस के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराएगी मोदी सरकार, कहा- केवल बजट संबंधित मुद्दे उठाए जाएंगे

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। केंद्र की मोदी सरकार संसद में पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने को फिलहाल तैयार नहीं है। सोमवार को सभी पार्टियों के साथ बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये जानकारी दी। इसी के साथ एक बात स्पष्ट हो गई है कि मानसून सत्र की तरह ही संसद का बजट सत्र भी हंगामेदार हो सकता है। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ हो गई। सत्र 8 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बीच में एक महीने का ब्रेक भी होगा।

संसद के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा पेगासस स्पाइवेयर का मुद्दा उठाए जाने के संबंध में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि यह मामला विचाराधीन है। उन्होंने कहा, 'हमने विपक्ष से कहा है कि बजट सत्र के पहले भाग के दौरान हम केवल बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए, एक अलग चर्चा करना संभव नहीं होगा। मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।'

सोमवार को ऑल-पार्टी मीट के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'कई पार्टियों ने पेगासस का मुद्दा उठाया है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति मामले की जांच कर रही है। इसलिए (बजट सत्र के पहले भाग में) बजट से संबंधित मुद्दों को ही उठाया जाना चाहिए।' प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज की सर्वदलीय बैठक में 25 दलों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, 'सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट सत्र के पहले भाग में केवल राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पेश किया जाता है।'

उन्होंने कहा, 'इस (पेगासस) मुद्दे पर जो कुछ भी कहने की जरूरत है, वह सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर पहले ही कह दिया था।' विपक्ष के कई सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आईटी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन दर्ज करने की मांग की है। इस पर जोशी ने आगे कहा, 'वे आगे बढ़ सकते हैं। इसे स्वीकार करना या न करना स्पीकर पर निर्भर करता है लेकिन इसमें कोई दम नजर नहीं आता।'

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 'सत्र के दूसरे भाग में अन्य मुद्दों को उठाया जा सकता है। हमने कहा है कि यदि पार्टियां संसद के सुचारू संचालन में सहयोग करती हैं, तो सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि यह सत्र सुचारू रूप से चलेगा।' इससे पहले राज्यसभा के सभावित व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार शाम को राजनातिक दलों के साथ अहम बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राज्यसभा के कामकाज के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान फैसला लिया गया कि बजट सत्र के पहले भाग में कोई विधायी कार्य नहीं होगा। धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट एजेंडे में होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने उन्हें सदन के संचालन में सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि बजट सत्र के दौरान संसद सुचारू रूप से चलेगी। बिड़ला ने सोमवार को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर विस्तार से होनी चाहिए चर्चा : ओम बिरला

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर विस्तार से चर्चा करने की वकालत करते हुए यह उम्मीद जताई कि सभी राजनीतिक दलों और सरकार के सहयोग से बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी।

बजट सत्र के दौरान लोक सभा में होने वाले कामकाज को तय करने के लिए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने सदन चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण और आम बजट पर व्यापकता के साथ विस्तार से चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही सांसद देश के महत्वपूर्ण मुद्दों और देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी सदन के अंदर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने बजट सत्र में लोक सभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों ने सदन को चलाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है।

उन्होंने इस आश्वासन के आधार पर यह उम्मीद जताई कि सभी दलों और सरकार के सहयोग से लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और सदन की कार्यवाही का परिणाम भी सामने आएगा जिससे देश की जनता का कल्याण हो सके।

किसान लम्बे संघर्ष के लिए तैयार रहें : राकेश टिकैत

नई दिल्ली, 31 जनवरी (एजेन्सी)। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को किसानों के मामले को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र पर देश के किसानों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। टिकैत ने कू करके कहा, 'देश के किसानों के साथ वादाखिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से यह स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें।'

भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के नेता टिकैत ने बीते शनिवार को कहा था कि किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनने तक लड़ाई जारी रहेगी। टिकैत ने एक ट्वीट में कहा, 'किसानों के परिवारों ने आंदोलन में अपने 700 से अधिक प्रियजनों को खो दिया है। किसान पिछले साल के इन दिनों को कभी नहीं भूलेंगे। एमएसपी किसानों की रीढ़ है और किसान चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून खेती का भविष्य बचाए! लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी।'

गौरतलब है कि पिछले साल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में आवश्यक विधेयक लाया जाएगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी।

चुनाव में भाजपा के खिलाप प्रचार किए जाने के सवाल पर टिकैत ने कहा, 'हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं राजनेता नहीं हूं, मैं राजनीतिक दलों से दूर रहता हूं। मैं केवल किसानों के मुद्दों के बारे में बात करता हूं और लोगों से अपने नेताओं से सवाल करने का आग्रह करता हूं। मैं किसानों के मुद्दे उठाता रहूंगा।'

साम्प्रदायिक मुद्दा छोड़ बेरोजगारी, शिक्षा पर सरकार क्यों नहीं करती बात : प्रियंका गांधी

नोएडा, 31 जनवरी (एजेन्सी)। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी पार्टी की महिला प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए नोएडा कैम्पेन करने पहुंचीं।

इस दौरान उन्होंने उत्तरप्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, सरकार 80-20 फीसदी की बात कर रही है, लेकिन सरकार यह क्यों नहीं बता रही है कि कितने फीसदी युवा बेरोजगार बेठे हुए हैं? शिक्षा के बजट में जितने फीसदी पैसे खर्च हुए हैं वो पहले से कम क्यों हो गए हैं? कितना फीसदी पैसा सेहत की सुविधाओं पर खर्च करेंगे? जातिवाद और साम्प्रदायिकता फैलाने से सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता है। जनता का इससे कोई फायदा नहीं है। जनता हर नेता को जवाब देह बनाए और उनसे अपनी परेशानियों को लेकर सवाल पूछें। सबसे आग्रह करना चाहती हूं, कि इस चुनाव को अपने लिए बनाइये।

इस दौरान जब आईएएनएस ने प्रियंका गांधी से युवाओं पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि, एनटीपीसी के छात्र परेशान हैं उनपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। दो सालों से यूपी में काम कर रही हूं। मैंने बार-बार देखा है जब परीक्षा आती है तो रद्द हो जाती है या फिर पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा होने के बाद कट ऑफ बदल जाती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, तमाम युवा ऐसे हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं। जो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा दी है तो नौकरी मिलेगी, बार बार घोटाला किए जा रहे हैं, जब वह आवाज उठा रहे हैं तो आप पीट रहे हैं। युवाओं पर ऐसी-ऐसी धाराएं लगाई जा रही है कि जेल चले जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं।

हमने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विधान बनाया है। इनको पढ़ें, क्योंकि हम ठोस बात कर रहें है इधर उधर की बात नहीं कर रहे।

प्रियंका गांधी ने आगे बताया कि, तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इधर-उधर की बात कर रही हैं। युवाओं के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं और न ही विकास की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने नौजवानों के लिए घोषणा पत्र निकाला है। सभी बोल देते हैं 20 लाख नौकरी देंगे, लेकिन यह रोजगार आएंगे कैसे इसके बारे में नहीं बताते।

कांग्रेस ने यह तय किया है कि हम युवाओं को बताएंगे कि यह रोजगार कैसे आएंगे। 12 लाख रोजगार सरकार में खाली पड़े हैं। हम किस तरह से भरेंगे, यदि आप अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार किस तरह आपकी मदद करेगी। हम यह बताएंगे।

पिछली बार नोएडा में कैम्पेन के दौरान कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा हुआ, आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं? इस सवाल के जवाब में प्रियंका बोलीं कि, जबसे मैं यूपी में काम कर रही हूं तब से मैं मानसिक रूप से तैयार हूं आप मुकदमा करिए, हिरासत में लीजिए, जेल में डालदें हम लड़ते रहेंगे।

विपक्ष आपको शून्य से आकलन कर रहा है? इस सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि, करने दीजिए, हम हर सीट पर लड़ रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं और हम करेंगे।

उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। साथ ही पहले चरण की शुरूआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से होगी और धीरे-धीरे कारवां बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जाकर समाप्त होगा।

यूपी में इस बार भी चुनाव पिछली बार की तरह वेस्ट यूपी से शुरू होंगे। वहीं आखिरी चरण पूर्वांचल में होगा, पहले चरण में 58 और आखिरी चरण में 64 विधानसभा सीटों में वोटिंग होगी।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com